राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

@swatantraprabhatmedia @swatantramedia RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) @SwatantraPrabhatonline news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, बुधवार, 11 फरवरी 2026

वर्ष 14,अंक 292, पृष्ट 04, मूल्यः 01 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें.....
9511151254

युवक की मौत मामले में तीन पर हत्या का केस दर्ज तालाब में मिला था शव..03

आदिवासी छात्रवास निर्माण में भू-माफिया बने बाधा, निर्माण कार्य रुकवाकर मजदूरों को दी धमकी..04

हाईकोर्ट ने गांधी को पढ़ने, निबंध लेखन कला को ध्यान में रखते हुए पॉक्सो दोषी की सज़ा कम की

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- बॉम्बे हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत सज़ा काट रहे एक व्यक्ति के सर्टिफिकेट्स और 'निबंध लेखन कला' को देखते हुए बीते सप्ताह उनकी सज़ा कम करने का फैसला किया है. हाईकोर्ट ने विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा आरोपी को दोषी ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखते हुए, उनकी सज़ा में नरमी बरतने का निर्णय लिया. इसमें अदालत ने जेल में रहते हुए निबंध लिखने समेत कई कार्यक्रमों में भाग लेने के चलते दोषी व्यक्ति की उम्रकैद की सज़ा को 12 साल में बदल दिया है. इसमें अन्य बातों के अलावा महात्मा गांधी के विचारों को पढ़ने, निबंध लिखने और पुस्तकों के विश्लेषण करने के कार्यक्रमों में भाग लेने से प्राप्त प्रमाण पत्रों को ध्यान में रखा गया है. उल्लेखनीय है कि घाटकोपर चॉल में रहने वाले अपिलकर्ता व्यक्ति की उम्र 20 साल थी, जब उसने दिसंबर 2016 में अपने पड़ोसी की पांच साल की बेटी का यौन उत्पीड़न किया था. इस मामले में उसे 2020 में दोषी ठहराया गया था. उच्च न्यायालय ने विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा आरोपी को दोषी ठहराने में कोई गलती नहीं पाई, लेकिन सज़ा की अवधि को आजीवन कारावास से घटाकर 12 साल करने के कई कारण बताए. अदालत के अनुसार, अपिलकर्ता पहले ही नौ साल से अधिक की सज़ा काट चुके हैं और जब यह अपराध किया था, तब उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था. इसके साथ ही अदालत ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि अभियुक्त को कोविड-19 के दौरान भी जमानत पर रिहा नहीं किया गया था. अदालत ने दोषी ठहराए गए व्यक्ति के जेल में रहते हुए प्राप्त किए गए तीन प्रमाण पत्रों पर भी ध्यान दिया, जिन्हें उनके वकीलों ओपी लालवानी और जिप्सन जॉन ने प्रस्तुत किया था।

न्यायाधीशों ने अपने आदेश में कहा कि इनमें पुणे स्थित तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ द्वारा 'पुस्तकों के विश्लेषण' कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जारी किया गया प्रमाण पत्र, मुंबई स्थित रामचंद्र प्रतिष्ठान द्वारा 'निबंध प्रतियोगिता' में भाग लेने के लिए जारी किया गया प्रमाण पत्र और मुंबई सर्वोदय मंडल द्वारा 'महात्मा गांधी के विचारों के अध्ययन' के लिए जारी किया गया प्रमाण पत्र शामिल है, जिसमें उन्होंने सफलतापूर्वक परीक्षा दी थी. इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस सारंग कोटवाल और संदेश पाटिल की खंडपीठ ने कहा, 'इन सभी कारकों पर सामूहिक रूप से विचार करने पर, हमें सज़ा सुनाते समय उनके प्रति कुछ नरमी दिखानी चाहिए.' न्यायाधीशों ने यह भी कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए, उन्होंने न्यूनतम 10 वर्ष की सज़ा से अधिक सज़ा सुनाई है. पीठ ने कहा, 'हमारी राय में 12 वर्ष की सज़ा न्यायसंगत होगी.' ये मामला 9 सितंबर 2016 का है, जब पीड़ित पांच साल की बच्ची पड़ोस में पानी भरने गई थी. उस समय अभियुक्त द्वारा उसे अपना गुप्तांग मुंह में रखने के लिए मजबूर किया गया था. इसके बाद वह बच्ची डरकर घर लौट आई और उसने अपनी मां को सब कुछ बताया. इस संबंध में पीड़िता की मां ने एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था।

हालांकि, कोर्ट ने अपीलकर्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि पीड़िता को उसके माता-पिता ने साजिश के तहत उनसे बदला लेने के लिए उनके खिलाफ गवाही देने ऐसे अपराध में फंसाने के लिए 'सिखाया' होगा. अदालत ने कहा, 'यह बहुत ही असंभव है कि पांच साल की छोटी बच्ची को आरोपी से कोई द्वेष हो या वह इस तरह की झूठी कहानी गढ़े. पीड़िता और उसकी मां का बयान बिल्कुल स्वाभाविक प्रतीत होता है. वे तुरंत थाने गए और बयान दर्ज कराया.' कोर्ट ने आगे कहा कि घटना के समय पीड़िता पांच साल की नाबालिग बच्ची थी. जब वह गवाह के रूप में पेश हुई तब वह आठ साल की थी. दर्ज साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसने तथ्यों को बहुत स्पष्ट रूप से और बिना किसी के सिखाए-पढ़ाए बताया था. इसलिए अदालत पाती है कि आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत अपराधों के संबंध में अभियोजन पक्ष ने अपना मामला संदेह से परे साबित कर दिया है।

मणिपुरः नगा-कुकी-जो हिंसा के बीच आगजनी और गोलीबारी की और घटनाएं, इंटरनेट बंद

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- मणिपुर के नगा-बहुल उखरुल ज़िले के लितान सारेखोंग इलाके में सोमवार (9 फरवरी) को भी तनाव बना रहा, जहां नगा और कुकी-जो समुदायों के सदस्यों के बीच लगातार दूसरे दिन आगजनी की घटनाएं हुईं. नगा-बहुल उखरुल ज़िले के लितान इलाके में मंगलवार सुबह कुकी-जो उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगा दी, जिससे दोनों समुदायों के बीच जारी जातीय तनाव और बढ़ गया. गोलीबारी की भी खबरें हैं. अखबार ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से बताया कि, रविवार और सोमवार के बीच दोनों समुदायों के 27-28 घर जला दिए गए. मंगलवार सुबह कितने घरों में आग लगाई गई, इसका सही आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. हालांकि, स्थानीय लोगों का दावा है कि दस से ज़्यादा घर जलाए गए. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू होने और सेना व अर्धसैनिक बलों की तैनाती के बावजूद हिंसा जारी है. हिंसा में दोनों समुदायों के लोगों को सुरक्षित जगहों पर भागना पड़ा. मंगलवार सुबह कई खाली घरों में आग लगा दी गई और गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद राज्य सरकार ने जिले में पांच दिनों के लिए इंटरनेट सर्विस बंद कर दी है. एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'हथियारबंद लोगों ने लितान सारेखोंग में खाली पड़े घरों में आग लगा दी और कई राउंड गोलियां चलाई. हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं और सुरक्षा बल स्थिति को काबू में लाने की कोशिश कर रहे हैं।'

उन्होंने बताया कि मणिपुर सरकार ने एहतियाती और निवारक कदम के तौर पर मंगलवार को उखरुल ज़िले के राजस्व क्षेत्राधिकार में ब्रॉडबैंड, वीपीएन और वी-सैट सहित सभी इंटरनेट सेवाओं को पांच दिनों के लिए निलंबित करने का आदेश दिया है।

अपने घरों से भागे स्थानीय लोगों ने इलाके में गोलीबारी न रोक पाने को लेकर सुरक्षा बलों से नाराज़गी जताई.

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि पिछले दो दिनों से लितान सारेखोंग और आसपास के कुकी गांवों से सैकड़ों कुकी और तंगखुल नगा ग्रामीण - जिनमें ज़्यादातर महिलाएं, बच्चे और बुज़ुर्ग हैं- सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे हैं. उन्होंने कहा, 'कई ग्रामीणों ने कुकी-बहुल कांगपोकपी ज़िले के मोटबुंग और साइकुल के कुछ हिस्सों में शरण ली है.' मणिपुर के मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने सोमवार को कहा था कि कम से कम 21 घर जला दिए गए हैं और स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। उन्होंने यह भी बताया कि हालात पर काबू पाने के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं. इस बीच, एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि दो ड्राइवर, जो अपने ट्रक खराब हो जाने के बाद लितान थाना क्षेत्र के अंतर्गत लमलाई चिंगफेई कुकी गांव में फंस गए थे, उन्हें सोमवार को सुरक्षित निकाल लिया गया. बता दें कि हाल ही में पिछले तीन साल से जातीय हिंसाग्रस्त मणिपुर में एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के एक साल बाद राज्य में नई सरकार बनी है. भाजपा नेता युमनाम खेमचंद नए मुख्यमंत्री बने. नई सरकार में तीन कुकी-ज़ो विधायकों के भागीदारी को लेकर भी नागरिक समाज संगठनों में नाराजगी है।

सोमवार को हिंसा में घायल कई लोगों को इंफाल स्थित रीजनल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़ में भर्ती कराया गया है. मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद सिंह ने घायलों से मुलाकात की और शांति व संयम की अपील करते हुए कहा कि मुद्दों का समाधान संवाद के ज़रिये किया जा सकता है. उखरुल के ज़िलाधिकारी आशीष दास ने कहा, 'कल रात 20 घर जला दिए गए. शुरुआत में पांच-छह घरों में आग लगाई गई थी, लेकिन तेज़ हवाओं के कारण आग तेज़ी से फैल गई.' सोमवार को हालात सामान्य करने के प्रयास जारी रहे और दोनों समुदायों के नागरिक समाज के नेताओं के बीच एक बैठक हुई. इस बैठक में उपमुख्यमंत्री लोसी दीखो, स्थानीय विधायक राम मुइवाह और साइकुल के विधायक किमनियो हैंगशिंग हाओकिप सहित अन्य लोग मौजूद थे. हालांकि, बैठक के तुरंत बाद एक और आगजनी की घटना हुई, जिसमें सात-आठ घर जलकर खाक हो गए. ज़िलाधिकारी ने कहा, 'प्रभावित परिवार और कुछ अन्य ग्रामीण आगे की परेशानी के डर से इलाका छोड़कर रिश्तेदारों के यहां शरण ले चुके हैं. स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है।'

निषेधाज्ञा लागू है और प्रभावित व संवेदनशील इलाकों में सेना तथा अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है.

यह हिंसा शनिवार रात तब भड़की, जब कथित तौर पर एक तंगखुल नगा व्यक्ति के साथ कुकी-जो समुदाय के कुछ लोगों ने मारपीट की. रविवार दोपहर को तनाव तब और बढ़ गया, जब नगा गांवों के लोग पास के एक कुकी गांव के मुखिया के पास पहुंचे और दोषियों को सामने लाने की मांग की. बाद में उसी शाम पत्थरबाज़ी हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी सहित कई लोग घायल हो गए. इसके बाद रात में आगजनी की घटनाएं हुईं. हिंसा के दौरान कथित तौर पर गोलियां चलाए जाने की भी खबर है. इस अशांति के कारण उखरुल और इंफाल घाटी के बीच सड़क संपर्क बाधित हो गया है. आम लोगों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकार ने मंगलवार को इंफाल-उखरुल-इंफाल मार्ग पर एक विशेष हेलीकॉप्टर उड़ान तय की है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, बुधवार के लिए दो अतिरिक्त हेलीकॉप्टर उड़ानों की योजना भी बनाई जा रही है।

संक्षिप्त ख़बरें

सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम व्हिसलब्लोअर के विरुद्ध एससी-एसटी एक्ट के तहत आरोप खारिज किए

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मध्य प्रदेश व्यापम परीक्षा घोटाले में एक व्हिसलब्लोअर आनंद राय के विरुद्ध जाति-आधारित हिंसा के आरोप खारिज कर दिए। आनंद राय ने 2022 में एक रैली के दौरान एक सांसद, विधायक और सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध कथित हिंसा और दु?र्व्यवहार के कारण हुए जाति-आधारित अत्याचार के मामले में आरोप तय करने के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एनके सिंह की पीठ ने राय की याचिका पर फैसला सुनाया और कहा, ''हमने एससी-एसटी एक्ट के दायरे पर चर्चा की है और कार्रवाई कानून के अनुसार नहीं है। अपील स्वीकार की जाती है।'' राय मध्य प्रदेश में आंखों के डाक्टर हैं और व्यापम परीक्षा घोटाले के व्हिसलब्लोअर में से एक हैं।

यह घटना 15 नवंबर, 2022 को रतलाम जिले के धराड़ गांव में बिरसा मुंडा जयंती के मौके पर भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति के अनावरण के लिए आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई। आरोप है कि राय ने एक सांसद, विधायक, कलेक्टर और दूसरे अधिकारियों की गाड़ियां रोकीं। विकास परगी नामक व्यक्ति ने एफआइआर दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि एक समूह ने करीब एक घंटे तक सड़क बंद रखी, सांसद-विधायक के साथ दु?र्व्यवहार किया और रास्ता खाली कराने की कोशिश कर रहे पुलिसवालों से हाथापाई की। एफआइआर में चिन्हित करीब 40-45 लोगों में राय का नाम भी था।

रतलाम के विशेष सत्र न्यायाधीश (एससी-एसटी एक्ट) ने 18 मार्च, 2025 को उनके विरुद्ध आरोप तय किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जनवरी, 2023 को इस मामले में राय को जमानत दे दी थी और बाद में एससी-एसटी एक्ट के तहत मुकदमे पर रोक लगा दी।

लैंबॉर्गिनी कांडः 'जो दोषी होता है, वह बचने के लिए...' कानपुर के DCP ने बताया- आरोपी शिवम कहां?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

कानपुर के लैंबॉर्गिनी कांड मामले में आरोपी कारोबारी का बेटा शिवम मिश्रा अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है. दो दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उसकी सही लोकेशन का पता पुलिस लगा नहीं पाई है. हालांकि, पुलिस का दावा है कि वह निरंतर मामले की जांच-पड़ताल में जुटी है. अब मामले में मंगलवार को डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव का बयान सामने आया है. उन्होंने बताया कि शिवम मिश्रा के पिता थाने में अपना बयान दर्ज कराने आए थे. कानपुर के वीआईपी रोड पर शनिवार दोपहर हुए लैंबॉर्गिनी कार एक्सीडेंट मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. इस घटना और पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों में काफी गुस्सा है. मामले में पुलिस ने पहले तो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज की थी, लेकिन बाद में वायरल वीडियो सामने आने के बाद आरोपी की पहचान तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के रूप में हुई थी।

नामजद एफआईआर दर्ज

नामजद FIR होते ही सोमवार को मामले के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर (IO) शैलेश पांडे कारोबारी केके मिश्रा के घर आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए पहुंचे थे. इस दौरान केके मिश्रा के घर का गेट नहीं खुला. इसके बाद IO को खाली हाथ ही थाने लौटना पड़ा. हालांकि, इसके बाद आरोपी पक्ष के वकील मृत्युंजय कुमार कारोबारी के घर पहुंचे थे. उनके लिए तुरंत गेट खुल गया. बाहर आने पर वकील मृत्युंजय कुमार ने एक ऐसा दावा किया, जिसने पूरी कहानी का ही पलटकर रख दिया है।

DCP सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव ने क्या कहा?

उन्होंने बताया कि लैंबॉर्गिनी कार शिवम मिश्रा नहीं, बल्कि उनके ड्राइवर चल रहे थे. इस लिए उन पर (शिवम) तो कोई मुकदमा ही नहीं बनता है. मामले में मंगलवार को डीसीपी सेंट्रल अतुल श्रीवास्तव का बयान सामने आया है. जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि शिवम मिश्रा के पिता आज थाने में आए थे और उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया है. आगे डीसीपी ने कहा कि देखिए जो दोषी होता है वह बचने के लिए तमाम तरीके अपनाता है. लेकिन पुलिस की जांच में या स्पष्ट है कि एक्सीडेंट के समय गाड़ी शिवम मिश्रा ही चला रहा था।

'दिल्ली में चल रहा शिवम का इलाज'

पुलिस इसी आधार पर जांच कर रही है. उन्होंने बताया कि शिवम मिश्रा के पिता ने कहा कि शिवम का इलाज दिल्ली के किसी अस्पताल में चल रहा है. पुलिस की टीमें उसकी तलाश में लगी हुई है।

सीतापुर में 5 साल की लापता बच्ची का झोपड़ी में मिला शव, गले पर रस्सी कसने के निशान

सीतापुर। बिसवां के काजीपुर गांव में सोमवार की दोपहर से लापता पांच वर्षीय बच्ची का खून से लथपथ शव गांव के बाहर एक झोपड़ी से बरामद हुआ। परिवारजन के मुताबिक, संध्या दोपहर में घर के पास खेलते हुए अचानक गायब हो गई थी। पिता रामशरण ने ग्रामीणों के साथ उसकी तलाश शुरू की। देर रात जब ग्रामीण गांव के बाहर एक झोपड़ी तक पहुंचे, तो बच्ची का शव देखकर सभी दंग रह गए। इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए। देर रात एसपी अंकुर अग्रवाल, एएसपी दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह और सीओ अमन सिंह भी मौके पर पहुंचे। बच्ची के गर्दन पर रस्सी से गला कसने के निशान पाए गए हैं। परिजन ने अज्ञात पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। सीओ बिसवां अमन सिंह ने कहा कि पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है। हत्या का मामला लग रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख कर जांच की दिशा तय होगी।

असम सीएम के नफ़रती भाषणों के ख़िलाफ़ याचिकाओं पर सुनवाई को सहमत हुआ सुप्रीम कोर्ट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली- सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा द्वारा राज्य के मुस्लिम समुदाय को लगातार निशाना बनाए जाने के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय करने पर सहमति जताई है. भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने इस याचिका को चुनाव के समय की एक 'समस्या' से जोड़ते हुए टिप्पणी की. कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नेता एनी राजा की याचिकाओं पर सीजेआई ने कहा कि 'समस्या यह है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, चुनाव का एक हिस्सा सुप्रीम कोर्ट के भीतर लड़ा जाता है.' वकील निज़ाम पाशा ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए कहा, 'हम इस माननीय अदालत से असम के वर्तमान मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे चिंताजनक भाषणों के संबंध में त्वरित हस्तक्षेप चाहते हैं, जिनमें हाल ही में पोस्ट किया गया एक वीडियो भी शामिल है, जिसमें उन्हें एक विशेष समुदाय के सदस्यों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है. शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, लेकिन कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई है।'

सीजेआई ने यह भी कहा, 'हम देखेंगे, तारीख देंगे.'

सीपीआई (एम) और एनी राजा ने अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की हैं, जिनमें शर्मा के खिलाफ हेट स्पीच और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से जुड़े अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने तथा मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठित करने की मांग की गई है. उल्लेखनीय है कि बीते हफ़्तों में शर्मा के द्वारा लगातार दिए जा रहे नफरती भाषणों के बाद बीते शनिवार भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की असम इकाई ने एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री को मुसलमानों पर गोली चलाते हुए दिखाया गया था. व्यापक निंदा के बीच इस वीडियो को डिलीट कर दिया गया. इस वीडियो को शर्मा के पहले से जारी सांप्रदायिक हमलों की एक अवैध और खतरनाक बढ़ोतरी बताया गया. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने लिखा कि यह गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत स्पष्ट अपराध बनता है. शर्मा पहले कह चुके हैं कि उनका काम 'मिया लोगों को परेशान करना' है. शर्मा ने 27 जनवरी को कहा था, 'कांग्रेस मुझे जितना चाहे गाली दे, मेरा काम मिया लोगों की ज़िंदगी मुश्किल बनाना है.' उन्होंने लोगों से समुदाय को किसी भी तरह परेशान करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा था, 'रिक्शा में अगर किराया 5 रुपये है, तो उन्हें 4 रुपये दीजिए. जब तक उन्हें परेशानी नहीं होगी, वे असम नहीं छोड़ेंगे... ये कोई मुद्दे नहीं हैं।'

उन्होंने कहा था कि हिमंता बिस्वा शर्मा और भाजपा सीधे तौर पर मियाओं के खिलाफ हैं. 'उल्लेखनीय है कि 'मिया' बांग्ला भाषी मुसलमानों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अपमानजनक शब्द है. असम की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अक्सर इस समुदाय को 'घुसपैठिए' कहती रही है. इन पर आरोप लगाया जाता रहा है कि वे मूल निवासियों के संसाधनों, नौकरियों और ज़मीन पर कब्ज़ा कर रहे हैं. याचिकाकर्ताओं ने 2021 से फरवरी 2026 तक की एक विस्तृत क्रोनोलॉजी पेश की है, जिसमें उन भाषणों और बयानों का विवरण है, जिनमें कथित तौर पर बंगाली मूल के मुसलमानों के सामाजिक, आर्थिक और नागरिक बहिष्कार की अपील की गई - जिसमें उनकी आजीविका, परिवहन, ज़मीन और मतदान अधिकारों से वंचित करने जैसे आह्वान भी शामिल हैं. याचिका में कहा गया है कि इन बयानों के ज़मीनी स्तर पर वास्तविक असर पड़े हैं - जिसमें आर्थिक भेदभाव, उत्पीड़न और बहिष्कार की घटनाओं को अपराधियों ने मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार कार्रवाई बताकर सही ठहराते रहे हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, याचिका यह भी तर्क देती है कि 'यह बयानबाज़ी जानबूझकर अवैध आप्रवासन (immigration) को मुस्लिम पहचान के साथ जोड़ देती है, जबकि आप्रवासन धर्म-निरपेक्ष विषय है और एनआरसी के आंकड़े दिखाते हैं कि बाहर किए गए लोगों में बहुसंख्यक गैर-मुस्लिम थे.' याचिका के अनुसार, इससे इन बयानों के पीछे की सांप्रदायिक और भेदभावपूर्ण मंशा उजागर होती है. इसके अलावा, 12 लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक और रिट याचिका भी दायर की गई है, जिसमें शर्मा के हेट स्पीच का मुद्दा उठाया गया है।

मंत्रियों और संवैधानिक पदाधिकारियों के 'असंवैधानिक' भाषणों पर रोक के लिए दिशानिर्देश की मांग

पूर्व सिविल सेवकों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, उद्यमियों और नागरिक समाज के सदस्यों सहित बारह नागरिकों के एक समूह ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों के भाषणों को 'अपमानजनक और बहिष्कार करने वाला' बताते हुए मुद्दा उठाया है. याचिकाकर्ताओं ने असम के मुख्यमंत्री की 'मिया मुसलमानों' पर हालिया टिप्पणियों का हवाला दिया है. कहा गया है कि मुख्यमंत्री पहले भी एक समुदाय से जुड़े नागरिकों को सब्ज़ियों की बढ़ती कीमतों, 'लव जिहाद' और यहां तक कि 'बाढ़ जिहाद' के लिए जिम्मेदार ठहरा चुके हैं. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने यह तक कहा है कि वे उस धार्मिक समूह से जुड़े चार से पांच लाख मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाना चाहते हैं. इसी तरह, अन्य उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के असंवैधानिक भाषणों का मुद्दा भी उठाया गया है. कहा गया है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बार-बार 'लैंड जिहाद' और 'लव जिहाद' का उल्लेख करते रहे हैं. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उर्दू भाषा के समर्थकों के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी अक्सर मुसलमानों को 'घुसपैठिए' और 'विदेशी समर्थक' कहते रहे हैं, और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने नागरिकों से 'इतिहास का बदला लेने' का आह्वान किया था।

याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि ऐसे भाषण, भले ही वे तकनीकी रूप से हेट स्पीच के कानूनी ढांचे में पूरी तरह न आते हों, लेकिन उनका समग्र प्रभाव संवैधानिक नैतिकता को कमजोर करता है और इन्हें अनियंत्रित नहीं छोड़ा जाना चाहिए. याचिका में कहा गया है, 'सार्वजनिक पदों पर बैठे लोग सामान्य वक्ता नहीं होते. उनके शब्दों पर राज्य की मुहर होती है, वे प्रशासनिक कार्रवाई को प्रभावित करते हैं, जनधारणा को आकार देते हैं और प्रत्यक्ष उकसावे या हेट स्पीच के बिना भी कमजोर समुदायों पर बहिष्करणकारी प्रभाव डाल सकते हैं.' याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को विभाजनकारी टिप्पणियां करने से रोकने के लिए दिशानिर्देश जारी करे।

राहुल गांधी का बड़ा आरोप- 'रक्षा मंत्री झूठ बोल रहे हैं, सच्चाई नरवणे की किताब में है'

पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की अप्रकाशित किताब 'फोर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी' (Four Stars of Destiny) को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि एक तरफ प्रकाशक 'पेंगुइन' कह रहा है कि किताब छपी ही नहीं, जबकि दूसरी तरफ खुद जनरल नरवणे ने सोशल मीडिया पर इसके उपलब्ध होने की बात कही थी। राहुल गांधी ने जनरल नरवणे का साल 2023 का एक पुराना ट्वीट दिखाते हुए दावा किया कि पूर्व सेना प्रमुख ने खुद लिंक साझा कर किताब के उपलब्ध होने की जानकारी दी थी। राहुल ने चुटकी लेते हुए कहा, या तो आप पेंगुइन की बात मान लें या पूर्व सेना प्रमुख की। जाहिर है, मैं एक जनरल पर भरोसा करूंगा।

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किताब में चीन के साथ 2020 के सीमा विवाद (कैलाश रेंज) पर जो सच लिखा गया है, वह प्रधानमंत्री और सरकार के लिए असहज करने वाला है। उन्होंने यह भी जोड़ा कि सरकार सच्चाई को दबाने के लिए पेंगुइन जैसी संस्थाओं का सहारा ले रही है। राहुल ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और लोकतंत्र से जुड़ा गंभीर मुद्दा बताते हुए कहा कि सरकार बहस से भाग रही है।

जब हार ने रच दी पहचान: टी20 विश्व कप में नेपाल का उदय

[पराजय नहीं, पहचान की शुरुआत: नेपाल का साहसी संघर्ष]
[चार रन की हार, करोड़ों दिलों की जीत: नेपाल क्रिकेट की गौरवगाथा]

जब इतिहास करवट बदलता है, तो वह शोर मचाकर नहीं आता, बल्कि मैदान पर उतरकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। 8 फरवरी 2026 की शाम वानखेड़े स्टेडियम में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। समुद्री हवा में घुली रोशनियों की चमक, हजारों दर्शकों की थमी सांसें और करोड़ों दिलों की उम्मीदें एक साथ स्पंदित हो रही थीं। यह कोई साधारण मुकाबला नहीं था, बल्कि छोटे सपनों और बड़े नामों के बीच होने वाली निर्णायक भिड़ंत थी। एक ओर दो बार का विश्व विजेता इंग्लैंड अपने अनुभव और प्रतिष्ठा के साथ खड़ा था, तो दूसरी ओर नेपाल, जिसके पास खिताब नहीं थे, लेकिन हौसलों की अपार पूंजी थी। उसी पल यह साफ हो गया था कि यह मुकाबला आंकड़ों का नहीं, बल्कि जज्बे और आत्मबल का संग्राम बनने वाला है। टॉस जीतकर इंग्लैंड ने जब पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, तो उसने अपने अनुभव और रणनीति पर पूरा भरोसा जताया। हालांकि शुरुआती ओवरों में ही नेपाल ने इस भरोसे को चुनौती दे दी। फिल साल्ट का जल्दी पवेलियन लौटना इंग्लैंड के लिए एक चेतावनी संकेत था। इसके बाद जोस बटलर ने कुछ रन जोड़े, लेकिन आउट होने के बाद टॉम बैंटन आए और जल्दी आउट हो गए, फिर जैकब बेथेल और कप्तान हैरी ब्रुक ने पारी को संभाला। दोनों ने संयम और आक्रमण का संतुलित प्रदर्शन करते हुए टीम को स्थिरता प्रदान की। हर रन के साथ इंग्लैंड की पारी मजबूत होती गई। ब्रुक का नेतृत्व और बेथेल की तकनीक यह साबित कर रही थी कि टीम दबाव में भी संतुलन बनाए रख सकती है, लेकिन नेपाल का आत्मविश्वास भी लगातार बढ़ता जा रहा था।

इस दौरान नेपाल के गेंदबाजों और फील्डरों की ऊर्जा और समर्पण देखते ही बनता था। दीपेंद्र सिंह ऐरी की घूमती गेंदों ने बल्लेबाजों को बार-बार भ्रमित किया, जबकि नंदन यादव ने सटीक लाइन-लेंथ से रन गति पर अंकुश लगाया और संदीप लामिछाने ने भी विकेट लेकर दबाव बनाया। फील्डर हर गेंद पर पूरे जोश से जुटे रहे– कभी बाउंड्री पर छलांग लगाकर, तो कभी तेज थ्रो से आसान रन रोककर। यह केवल एक मुकाबला नहीं था, बल्कि अपनी पहचान स्थापित करने का दृढ़ संकल्प था। अंत में विल जैक्स की विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड 184 रन तक पहुंचा, जो मजबूत जरूर था, लेकिन नेपाल के हौसलों को तोड़ने के लिए पर्याप्त नहीं लग रहा था। लक्ष्य का पीछा करते हुए नेपाल ने शुरुआत से ही यह स्पष्ट कर दिया कि वह डर और दबाव से मुक्त होकर खेलने आया है। कुशल भुर्तेल ने आसिफ शेख के साथ आक्रामक शुरुआत की और बड़े शॉट लगाकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर दबाव बना दिया। आसिफ के आउट होने के बाद रोहित पौडेल ने धैर्य और समझदारी से पारी को आगे बढ़ाया, हालांकि कुशल भुर्तेल भी जल्द आउट हो गए। फिर दीपेंद्र सिंह ऐरी के साथ उन्होंने टीम को मजबूत आधार प्रदान किया। हर चौके और छक्के के साथ स्टेडियम का शोर बढ़ता गया और दर्शकों को महसूस होने लगा कि वे किसी ऐतिहासिक पल के साक्षी बन रहे हैं। यह केवल रन चेज नहीं था, बल्कि आत्मसम्मान और विश्वास की यात्रा थी।

मध्य ओवरों में दीपेंद्र सिंह ऐरी ने जिम्मेदारी का शानदार निर्वाह किया। उन्होंने परिस्थितियों को भांपते हुए सटीक शॉट्स लगाए और रन गति को बनाए रखा। नेपाल की पारी की सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि कोई भी खिलाड़ी घबराया हुआ नजर नहीं आया। सभी को अपने लक्ष्य और क्षमता पर पूरा भरोसा था। इसके बाद आरिफ शेख आए लेकिन जल्द आउट हो गए, फिर लोकेश बाम मैदान में आए और उन्होंने मैच की दिशा ही बदल दी, हालांकि गुलशन झा के जल्दी आउट होने से दबाव बढ़ा। उनकी बल्लेबाजी में निडरता, परिपक्वता और जुनून का अद्भुत मेल दिखाई दिया। जोफ्रा आर्चर जैसे विश्वस्तरीय गेंदबाज पर लगाए गए छक्के सिर्फ रन नहीं थे, बल्कि नेपाल के बढ़ते आत्मविश्वास की सशक्त घोषणा थे। जैसे-जैसे मैच अंतिम ओवर की ओर बढ़ा, तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। जीत के लिए दस रन चाहिए थे और लाखों दिल एक साथ धड़क रहे थे। स्टेडियम में सन्नाटा और उम्मीद दोनों की मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। सैम करन ने इस दबाव भरे क्षण में अद्भुत संयम और समझदारी का परिचय दिया। उन्होंने सटीक लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए नेपाल के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का अवसर नहीं दिया। केवल पांच रन बने और इंग्लैंड चार रन से विजयी हो गया। स्कोरबोर्ड ने इंग्लैंड को विजेता बताया, लेकिन मैदान पर नेपाल का साहस सबसे ऊंचा नजर आ रहा था। यह हार नहीं, बल्कि एक नई पहचान की मुहर थी।

यह मुकाबला आधुनिक क्रिकेट की बदलती तस्वीर का सशक्त प्रतीक बन गया। अब एसोसिएट टीमें केवल अनुभव जुटाने नहीं, बल्कि इतिहास रचने के इरादे से मैदान में उतर रही हैं। नेपाल, स्कॉटलैंड और नामीबिया जैसी टीमें यह साबित कर रही हैं कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। सीमित सुविधाओं के बावजूद उन्होंने अनुशासन, मेहनत और आत्मविश्वास से खुद को मजबूत बनाया है। इस मैच के बाद नेपाल के युवा खिलाड़ी वैश्विक मंच पर चर्चा का विषय बन गए और विशेषज्ञों ने उन्हें भविष्य का उज्ज्वल सितारा बताया। टी20 विश्व कप 2026 की यह शुरुआत क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक अविस्मरणीय और भावनात्मक स्मृति बन गई। इस मुकाबले ने यह स्पष्ट कर दिया कि क्रिकेट की असली सुंदरता उसकी अनिश्चितता, रोमांच और भावनात्मक गहराई में ही बसती है। नेपाल ने यह साबित कर दिया कि सपनों का मूल्य केवल पदकों और ट्रॉफियों से नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष, आत्मविश्वास और संकल्प से आंका जाता है। भले ही वे चार रन से हार गए, लेकिन उन्होंने करोड़ों दिलों में सम्मान और प्रेरणा की अमिट छाप छोड़ दी। यह मैच सदैव इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में अंकित रहेगा–उस अविस्मरणीय दिन के रूप में, जब एक छोटे से देश ने अपने विशाल हौसलों, अडिग विश्वास और अदम्य जुझारूपन से पूरी दुनिया को मंत्रमुग्ध कर दिया और क्रिकेट को नई सोच, नई ऊर्जा तथा नई पहचान प्रदान की।

प्रो. आरके जैन

देश के आर्थिक विकास को भ्रमित करती वर्ग विषमताएं

अर्थतंत्र से मजबूत होती देश की अधो संरचना।

देश की सामाजिक विषमताओं ने समाज में कई समस्याओं को जन्म दिया है एवं आर्थिक प्रगति पर विभिन्न सोपानों में लगाम लगाई है। भारतीय समाज में विषमता एवं विविधता भारत के लिए एक बड़ी समस्या बनकर सामने खड़ी है। स्वतंत्रता के पूर्व तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाज में विषमताएं भारत के लिए चुनौती बनकर वर्तमान में कई बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। आज जातिगत संघर्ष बढ़ गए हैं,जातिगत संघर्षों को राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने बहुत क्लिष्ट बना दिया है। राजनीति सदैव महत्वाकांक्षा के बल पर जातिगत समीकरण को नए-नए रूप तथा आयाम देती आई है और सदैव समाज में वर्ग विभेद आर्थिक विभेद कर के अपना उल्लू सीधा करना मुख्य ध्येय बन चुका है। उच्च वर्ग तथा निम्न वर्ग सदैव सत्ता के संघर्ष के लिए न सिर्फ एक दूसरे का परस्पर विरोध करते है बल्कि शासन प्रशासन के विरोध में भी सदैव खड़े पाए गए हैं। सत्ता पाने की लालसा में जातीय संघर्ष, नक्सलवाद तेजी से समाज में पनपता जा रहा है। भारतीय परिपेक्ष में आज सिर्फ जाती ही नहीं धार्मिक महत्वाकांक्षा देश के समाज के समक्ष चुनौती बन गया है। भारत में हिंदू मुस्लिम जाति संघर्ष ऐतिहासिक तौर पर अपनी जड़ें जमां चुका है, वर्तमान में मंदिर और मस्जिद के झगड़े देश में अशांत माहौल पैदा करने का एक बड़ा सबक बन चुके है।और यही वर्ग विभेद संघर्ष भारतीय आर्थिक विकास के बीच एक बड़ा अवरोध बनकर खड़ा है। पश्चिमी विद्वान भी कहते हैं कि भारत के राष्ट्र के रूप में विकसित होने में जाति एवं धर्म ही सबसे बड़ी बाधाएं हैं जिन्हें दूर करना सर्वाधिक कठिन कार्य है क्योंकि इसकी जड़ें भारत के स्वतंत्रता के पूर्व से देश में गहराई लिए हुए हैं। जातीय वर्ग संघर्ष और भाषाई विवाद ऐसा मुद्दा रहा है जिससे लगभग एक शताब्दी तक भारत आक्रांत रहा है। आजादी के बाद से ही भाषा विवाद को लेकर कई आंदोलन हुए खासकर दक्षिण भारत राज्यों द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने एवं देश पर हिंदी थोपे जाने के विरोध में विरोध प्रदर्शनों को प्रोत्साहित किया गया। आज भी विभिन्न राज्यों में भाषाई विवाद एक ज्वलंत एवं संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है, चाहे वह बंगाल हो, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा और महाराष्ट्र में भी भाषाई विवाद अलग-अलग स्तर पर सतह पर पाए गए हैं। समान सिविल संहिता को लेकर बहुसंख्यक संविधान में आक्रोश है दूसरी तरफ अल्पसंख्यक समुदाय इसलिए डरा हुआ है कि कहीं उसकी अपनी अस्मिता एवं पहचान अस्तित्व हीन ना हो जाए। स्वतंत्रता के बाद से यह विकास की मूल धारणा थी कि पंचवर्षीय योजनाओं में वर्ग विहीन समाज में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष तरीके से समाज का आर्थिक विकास तथा रोजगार के साधन उपलब्ध हो सकेंगे। पर स्वतंत्रता के 75 साल के बाद भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वर्ग विभेद भाषाई विवाद ने अभी भी आर्थिक विकास में कई बाधाएं उत्पन्न की है। संविधान में सदैव सकारात्मक वर्ग विभेद एवं विकास की अवधारणा को प्रमुखता से शामिल किया गया था और पंचवर्षीय योजनाओं में भी विकास को वर्ग विभेद से अलग रखकर विकास की अवधारणा को बलवती बनाया गया है। सामाजिक आर्थिक तथा धार्मिक विविधता वाले समाज को विवादों से परे रख आर्थिक विकास की परिकल्पना एक कठिन और दुष्कर अभियान जरूर है पर असंभव नहीं है। और इसी की परिकल्पना को लेकर आजादी के पश्चात से पंचवर्षीय योजनाओं का प्रादुर्भाव सरकार ने समय-समय पर लागू किया है। विकास की अवधारणा में राष्ट्र की मुख्य धारा में समाज के पिछड़े वर्ग को शामिल कर उन्हें सम्मुख लाना होगा। यदि देश के पिछड़ा वर्ग और गरीब तबका विकास की मुख्यधारा से जुड़ता है तो गरीबी, भुखमरी, नक्सलवाद जैसे संकट अस्तित्व हीन हो जाएंगे और ऐसी समस्या धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। आवश्यकता यह है कि हमें राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानकर इस पर अमल करना होगा। फिर चाहे वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हो या समावेशी राष्ट्रवाद हो। समाज की मुख्यधारा में राष्ट्रवाद को एक प्रमुख अस्त्र बनाकर देश की प्रगति में इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। भारत में आजादी के 75 वर्ष बाद भी ब्रिटिश हुकूमत की तरह गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, नक्सलवाद, आतंकवाद, सांप्रदायिकता,भाषावाद एवं क्षेत्रीय विघटनकारी प्रवृत्तियां सर उठाये घूम रही हैं, हम इन पर अभी तक प्रभावी नियंत्रण नहीं लगा पाए हैं। हमें इन सब विसंगतियों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय नागरिकता एवं भारत राष्ट्र की विकास की अवधारणा को राष्ट्रवाद से जोड़कर आर्थिक विकास को एक नया आयाम देना होगा,तब जाकर भारत वैश्विक स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत एवं आत्मनिर्भर बन सकेगा।

संजीव ठाकुर

मोबाइल, नेटवर्क और सपने: लेकिन महिलाएं अब भी बाहर क्यों?

डिजिटल बराबरी का अधूरा सपना और भारतीय महिलाएं
इंटरनेट के दौर में स्त्री का संघर्ष: सुविधा से सम्मान तक

हर सुबह घर में रोशनी से पहले जिम्मेदारियां जाग जाती हैं, और उसी के साथ एक महिला भी। मोबाइल की चमक दीवारों तक पहुंचती है, लेकिन उसकी हथेली तक नहीं। वह चूल्हे की आग में अपनी थकान घोलती है, बच्चों के सपनों को आकार देती है, पानी की कतार में खड़ी होकर दिन की नींव रखती है। उसी घर में रखा फोन किसी और की उंगलियों में पूरी दुनिया समेटे रहता है, जबकि वह अपने ही घर में डिजिटल अंधेरे में जीती रहती है। चमकते नारों और विज्ञापनों के पीछे एक दबा हुआ दर्द छिपा है, जहां करोड़ों महिलाएं तकनीक के दरवाजे पर खड़ी होकर भी भीतर नहीं जा पातीं। उनके पास घर है, रिश्ते हैं, जिम्मेदारियां हैं, लेकिन अपने भविष्य को गढ़ने का डिजिटल अधिकार नहीं है। यह कहानी सुविधा की नहीं, छीनी गई पहचान की पीड़ा है। भारत गर्व के साथ खुद को तकनीकी शक्ति कहता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और वर्चुअल शिक्षा आधुनिकता के प्रतीक बन चुके हैं। शहरों की ऊंची इमारतों से लेकर गांव की कच्ची गलियों तक इंटरनेट की लहर दौड़ रही है। लेकिन इस विकास के रंगमंच पर महिलाओं की भूमिका अक्सर दर्शक की बनी रहती है। ग्रामीण और मध्यमवर्गीय घरों में स्मार्टफोन आज भी पुरुषों की निजी जागीर समझा जाता है। महिलाएं अनुमति की दहलीज लांघकर ही उसे छू पाती हैं। सरकारी योजनाओं, नौकरी के पोर्टलों और बैंकिंग ऐप्स तक उनकी पहुंच अधूरी रहती है। यह अधूरापन उन्हें हर दिन प्रगति की दौड़ में और पीछे धकेल देता है।

इस डिजिटल दूरी की जड़ें नेटवर्क की कमजोरी में नहीं, बल्कि सदियों पुरानी मानसिकता में गहराई तक धंसी हुई हैं। आज भी कई घरों में फोन महिलाओं की स्वतंत्रता पर पहरा माना जाता है। उनकी आज़ादी को संदेह और नियंत्रण की जंजीरों में जकड़ दिया जाता है। डिजिटल शिक्षा के अभाव में वे खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। उन्हें हर क्लिक से डर लगता है, हर लिंक में खतरा नजर आता है। साइबर अपराध, डीपफेक और ऑनलाइन अपमान का भय उनके मन में स्थायी साया बनकर बैठ जाता है। यह डर धीरे धीरे उनकी जिज्ञासा, आत्मसम्मान और आगे बढ़ने की इच्छा को खामोशी से निगल जाता है। घर की चारदीवारी के भीतर महिलाओं पर टिका अदृश्य बोझ इस असमानता को और मजबूत करता है। बिना किसी वेतन, सम्मान या अवकाश के वे दिनभर चूल्हे, बच्चों, बुजुर्गों और जरूरतों के बीच खुद को खपा देती हैं। उनका हर दिन दूसरों के लिए शुरू होता है और दूसरों पर ही खत्म हो जाता है। सीखने, समझने और आगे बढ़ने के लिए उनके पास न समय बचता है, न ऊर्जा। गांवों में पानी और ईंधन की तलाश लड़कियों की पढ़ाई और डिजिटल दुनिया दोनों छीन लेती है। तकनीक उनके लिए एक दूर चमकता सपना बन जाती है, जिसे वे सिर्फ दूसरों की उंगलियों में साकार होते देखती हैं।

इस डिजिटल खाई का सबसे गहरा घाव महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता पर पड़ता है। आज रोज़गार और कमाई के नए रास्ते इंटरनेट की गलियों से होकर गुजरते हैं। ऑनलाइन व्यापार, फ्रीलांसिंग, डिजिटल सेवाएं और गिग वर्क उन्हें आत्मनिर्भर बना सकते थे। लेकिन साधनों की कमी उनके सपनों पर ताला लगा देती है। किसान महिलाएं आधुनिक तकनीक से वंचित रहकर कम उपज और कम आय तक सीमित रह जाती हैं। मध्यमवर्गीय महिलाएं घर बैठे काम करने के अवसर खो देती हैं। उनकी मेहनत, प्रतिभा और हुनर बाजार की रोशनी तक पहुंच ही नहीं पाते। जमीनी सच्चाइयों की कहानियां इस पीड़ा को और तीखा बना देती हैं। कोई महिला महीनों की मेहनत से बनाई गई हस्तकला को ऑनलाइन मंच नहीं दे पाती। कोई छात्रा कमजोर नेटवर्क के कारण अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देती है। कोई बीमार महिला डॉक्टर से संपर्क न कर पाने के कारण चुपचाप दर्द सहती रहती है। कई महिलाएं सोशल मीडिया पर अपमान, धमकी और ट्रोलिंग के डर से अपनी आवाज दबा लेती हैं। वे धीरे धीरे पीछे हट जाती हैं, जैसे खामोशी ही उनकी नियति बन गई हो।

सरकार और संस्थाओं ने बदलाव की कोशिशें जरूर की हैं, लेकिन वे अब भी अधूरी और कमजोर हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू होते हैं, पर महिलाओं तक सही ढंग से नहीं पहुंच पाते। नेटवर्क गांवों की सीमाओं पर आकर दम तोड़ देता है। डेटा गरीब महिलाओं के लिए आज भी भारी बोझ बना हुआ है। साइबर सुरक्षा कानून और सहायता तंत्र कमजोर हैं। नीतियां कागजों पर आकर्षक दिखती हैं, लेकिन जमीन पर उनका असर फीका पड़ जाता है। जब तक योजनाएं महिलाओं की वास्तविक जिंदगी और जरूरतों से नहीं जुड़ेंगी, तब तक डिजिटल बराबरी का सपना अधूरा ही रहेगा। यह डिजिटल असमानता केवल वर्तमान की समस्या नहीं है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों की किस्मत भी तय कर रही है। जब एक मां तकनीक की दुनिया से बाहर रह जाती है, तो उसकी बेटी भी आत्मविश्वास और अवसरों से वंचित हो जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में यह दूरी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली जाती है। समाज में जब आत्मनिर्भर और सशक्त महिलाओं की संख्या घटती है, तो विकास की रफ्तार खुद ही थमने लगती है। तकनीकी क्षेत्रों में महिलाओं की कमजोर मौजूदगी देश की रचनात्मकता और नवाचार शक्ति को खोखला कर देती है। यह पराजय सिर्फ महिलाओं की नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की सामूहिक हार बन जाती है।

अब आधे-अधूरे प्रयासों का समय बीत चुका है, यह निर्णायक बदलाव का क्षण है। महिलाओं के लिए हर गांव और हर मोहल्ले में डिजिटल प्रशिक्षण केंद्र बनने चाहिए। हर लड़की और हर महिला को सस्ता, सुरक्षित और निजी स्मार्टफोन मिलना चाहिए। परिवारों में यह चेतना जागृत करनी होगी कि मोबाइल आज विलासिता नहीं, बल्कि शिक्षा, रोजगार और सम्मान का साधन है। साइबर सुरक्षा और डिजिटल अधिकारों की शिक्षा अनिवार्य बनानी होगी। गांवों में मजबूत नेटवर्क, सामुदायिक इंटरनेट केंद्र और तकनीकी सहायता केंद्र स्थापित करने होंगे। साथ ही महिलाओं को डिजिटल उद्यमिता के लिए वित्त, मार्गदर्शन और बाजार से जोड़ना होगा। कल्पना नहीं, अब एक नए भारत की जरूरत है – ऐसा भारत जहां किसी महिला की सुबह चूल्हे की आग से नहीं, बल्कि उसके अपने मोबाइल की रोशनी से शुरू हो। जहां वह डर और अनुमति के बिना बैंकिंग करे, पढ़ाई करे, कारोबार बढ़ाए और दुनिया से बराबरी के साथ संवाद करे। जहां तकनीक उसकी सीमाएं तय न करे, बल्कि उसके सपनों को दिशा और गति दे। जहां डिजिटल समानता सिर्फ सरकारी दस्तावेजों की भाषा न होकर हर घर की सच्चाई बने। यह सवाल सुविधा का नहीं, बल्कि सम्मान, अधिकार और आत्मसम्मान का है। जिस दिन हर महिला डिजिटल रूप से सशक्त होगी, उसी दिन भारत सच मायनों में विकसित कहलाएगा। अब वक्त आ गया है कि फोन केवल घर में मौजूद न रहे, बल्कि हर महिला के हाथ में उसकी ताकत बनकर पहुंचे।

कृति आरके जैन

संपादकीय

कोशिश से हरियाली तक जब गांव खुद अपने भविष्य की जड़ें सींचते हैं

महाराष्ट्र और कर्नाटक के कुछ गांवों में चल रही पर्यावरणीय पहलें आज उस भारत की तस्वीर दिखाती हैं, जहां समाधान किसी आदेश या योजना का इंतज़ार नहीं करते, बल्कि ज़मीन से उठते हैं। यह कहानी केवल पेड़ लगाने की नहीं है, बल्कि सोच बदलने, जिम्मेदारी लेने और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित भविष्य गढ़ने की है। सोलापुर के पथरीले गांवों से लेकर धुले के जंगलों और बेंगलुरु के बाहरी इलाके के एक छोटे से गांव तक, लोगों ने साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो हरियाली असंभव नहीं रहती। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के माडा तहसील के अंजनगांव खिलोबा में किसान प्रमोद इंगले जिस जमीन पर जंगल उगा रहे हैं, वह कभी झाड़ियों से आगे कुछ नहीं जानती थी। पथरीली जमीन, कम पानी और तेज गर्मी इन सबके बीच पेड़ लगाना एक सपना सा लगता था। लेकिन इंगले और उनके गांव के 25 साथी इस सपने को रोज़ अपने हाथों से सच कर रहे हैं। वे पौधों की जड़ों के पास गन्ने के सूखे अवशेष बिछाते हैं ताकि नमी बनी रहे और पानी की बर्बादी न हो। यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि स्थानीय समझ और अनुभव का नतीजा है। इन सौ पेड़ों को बचाने की जिम्मेदारी पूरे गांव ने साझा की है, क्योंकि उन्हें पता है कि पेड़ लगाना आसान है, उन्हें जिंदा रखना असली चुनौती है। अंजनगांव की यह पहल अकेली नहीं है। सोलापुर जिले के 43 गांवों और दो कस्बों में अब तक छह हजार से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं और उनकी देखभाल भी की जा रही है। इन गांवों में पर्यावरण पाठशालाएं लगती हैं, जहां डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती हैं और धरती के बढ़ते तापमान के खतरों को सरल भाषा में समझाया जाता है। पूर्व आईआरएस अधिकारी विपुल वाघमारे के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान का नारा है- 'लेट्स प्लांट ए ट्री इन द माइंड।' यानी पहले सोच में बदलाव, फिर जमीन पर काम। गांवों में दस लोगों की टीम जाकर पर्यावरण परिवर्तन, जल संकट और पौधरोपण की जरूरत पर बात करती है। इसके बाद ग्रामीण खुद समूह बनाकर सौ पेड़ लगाने और उन्हें बचाने का लक्ष्य तय करते हैं। यह प्रक्रिया लोगों को सिर्फ सहभागी नहीं, बल्कि मालिक बनाती है।

इन गांवों में पेड़ों की देखभाल के लिए हर दस दिन में चंदा इकट्ठा किया जाता है। टैंकर से पानी लाया जाता है, खर्च सब मिलकर उठाते हैं। प्रमोद इंगले कहते हैं कि वे केवल आज के लिए नहीं, अपने बच्चों के कल के लिए यह सब कर रहे हैं। उनके शब्दों में, अगर पेड़ रहेंगे तभी बच्चे सुरक्षित रह सकेंगे। यह सोच पर्यावरण को किसी दूर की समस्या से निकालकर रोज़मर्रा की जिम्मेदारी बना देती है।

महाराष्ट्र के ही धुले जिले के पिंपलनेर, साक्री तहसील का डवण्यापाडा जंगल एक और उदाहरण है, जहां समुदाय ने जंगल को अपना माना। 1100 हेक्टेयर में फैले इस जंगल की सुरक्षा के लिए गांव वालों ने गार्ड नियुक्त किए हैं और खुद भी बारी-बारी से रखवाली करते हैं। सात बस्तियों के हर घर से सालाना 300 रुपये लेकर गार्ड की सैलरी दी जाती है। इससे अवैध कटाई रुकी है और अतिक्रमण पर भी रोक लगी है। गांव वालों ने कड़े नियम बनाए हैं।जंगल में कुल्हाड़ी ले जाना मना है, हरे पेड़ काटने पर भारी जुर्माना है और हर घटना का पंचनामा कर वन विभाग को सौंपा जाता है। यह अनुशासन डर से नहीं, साझा जिम्मेदारी से पैदा हुआ है।

इन पहलों के बीच एक और महत्वपूर्ण कहानी कर्नाटक के बेंगलुरु के बाहरी इलाके के बिलपुरा पंचायत की है, जहां पर्यावरण संरक्षण घर की चौखट से शुरू होता है। यह गांव दिखाता है कि कचरा समस्या नहीं, संसाधन बन सकता है। कभी जहां खुले मैदानों में कचरे के ढेर, बदबू और धुआं आम था, आज वहां 90 प्रतिशत कचरा घरों में ही अलग किया जाता है। गीले कचरे से खाद बनती है और उसी खाद से गांव में फलदार पेड़ों का एक छोटा सा वन तैयार हो रहा है। बिलपुरा की इस सफलता के केंद्र में घरों में बनने वाली खाद है, खासकर महिलाओं की भूमिका। गांव की महिलाएं रसोई से निकलने वाले गीले कचरे को अलग रखती हैं, उसे खाद में बदलने की प्रक्रिया अपनाती हैं और फिर उसी खाद का इस्तेमाल अपने आंगन, खेत और सामुदायिक जमीन पर करती हैं। यह काम किसी बड़े बजट या भारी मशीनरी से नहीं हुआ, बल्कि पंचायत, गांव वालों और पास की अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के छात्रों और शिक्षकों के सहयोग से संभव हुआ। उन्होंने ग्रामीणों को समझाया कि कचरा हम बनाते हैं, तो उसे संभालना भी हमारी जिम्मेदारी है।

घरों में खाद बनाना केवल पर्यावरण के लिए नहीं, सामाजिक बदलाव के लिए भी अहम साबित हुआ है। जब महिलाएं कचरे को अलग करती हैं, खाद बनाती हैं और पेड़ उगते देखती हैं, तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। रसोई का कचरा, जिसे पहले बेकार समझा जाता था, अब गांव की हरियाली की नींव बन गया है। इससे मिट्टी की सेहत सुधरी है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम हुई है और गांव का खर्च भी घटा है। सबसे बड़ी बात यह कि बच्चों ने अपनी आंखों के सामने कचरे से जंगल बनते देखा है, जो उन्हें जीवन भर याद रहेगा।

इन सभी कहानियों को जोड़ने वाली एक डोर है स्थानीय पहल और सामूहिक जिम्मेदारी। कहीं पेड़ बचाने के लिए चंदा है, कहीं जंगल बचाने के लिए नियम, तो कहीं घर-घर में खाद बनाने की आदत। ये पहलें बताती हैं कि पर्यावरण संरक्षण कोई एक बड़ा कदम नहीं, बल्कि छोटे-छोटे सतत प्रयासों का नतीजा है। जब गांव यह समझ लेते हैं कि तापमान बढ़ने, पानी घटने और जंगल कटने का असर सबसे पहले उन्हीं पर पड़ेगा, तब समाधान भी वहीं से निकलते हैं।

आज जब शहर कचरा प्रबंधन, हरियाली और जल संकट से जूझ रहे हैं, तब ये गांव एक रास्ता दिखाते हैं। घरों में खाद बनाना, पेड़ों को बचाने के लिए सामूहिक खर्च उठाना और जंगल की रखवाली खुद करना ये सब ऐसे कदम हैं, जिन्हें कहीं भी अपनाया जा सकता है। जरूरत केवल सोच बदलने की है। इन गांवों ने साबित किया है कि अगर हम अपने आसपास से शुरुआत करें, तो धरती को बचाने की कोशिश रंग ला सकती है। यह कोशिश ही भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी है।

कांतिलाल मांडोत

क्या था एपस्टीन का बेबी रैंच प्लान

जेफ्री एपस्टीन का तथाकथित बेबी रैंच विचार आधुनिक समय के सबसे डरावने और विचलित करने वाले प्रसंगों में से एक माना जाता है। यह कोई औपचारिक योजना या लिखित परियोजना नहीं थीए बल्कि उसकी निजी बातचीतोंए दंभ भरी चर्चाओं और शक्ति प्रदर्शन से उपजा हुआ एक ऐसा विचार थाए जिसने उसके चरित्रए मानसिकता और नैतिक दिवालियेपन को उजागर कर दिया। यह विचार केवल व्यक्तिगत सनक नहीं थाए बल्कि उस सोच का विस्तार था जिसमें धनए प्रभाव और सत्ता के बल पर इंसानी जीवन को प्रयोग की वस्तु समझा जाता है। एपस्टीन स्वयं को असाधारण बुद्धिमान मानता था। उसे यह भ्रम था कि उसके भीतर कुछ ऐसा विशेष है जो सामान्य मनुष्यों से उसे श्रेष्ठ बनाता है। इसी आत्ममुग्धता से यह विचार जन्मा कि यदि उसके जैविक गुणों से अनेक संतानें पैदा की जाएँए तो एक प्रकार की श्रेष्ठ मानव पीढ़ी अस्तित्व में आ सकती है। उसने न्यू मैक्सिको क्षेत्र में स्थित अपने विशाल और एकांत रैंच को इस कल्पना का केंद्र माना। उसके अनुसार यह स्थान इतना दूरदराज़ और सुरक्षित था कि वहाँ बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के उसकी मर्जी के प्रयोग किए जा सकते थे। उसकी कल्पना में यह रैंच केवल निवास स्थान नहीं थाए बल्कि एक प्रजनन केंद्र जैसा थाए जहाँ अनेक युवतियों को लाकर उनसे गर्भधारण कराया जाता और इस प्रक्रिया से उत्पन्न बच्चों को भविष्य के असाधारण मनुष्य के रूप में देखा जाता। वह बार बार यह कहता था कि इतिहास में कुछ लोगों ने महान बुद्धिजीवियों के जैविक तत्वों को संचित करने की कोशिश की थी और वही परंपरा वह और आगे ले जाना चाहता है। फर्क केवल इतना था कि वह स्वयं को उसी महानता का प्रतीक मान बैठा था। इस विचार की भयावहता केवल इसकी अव्यवहारिकता में नहीं थीए बल्कि उस दृष्टि में थी जिसमें स्त्रियों को स्वतंत्र मनुष्य नहींए बल्कि साधन के रूप में देखा गया। उसके लिए मातृत्व कोई भावनात्मक या सामाजिक अनुभव नहीं थाए बल्कि एक यांत्रिक प्रक्रिया थी। स्त्री का शरीर उसके लिए प्रयोगशाला बन गया था और गर्भ एक परियोजना। यही कारण है कि जिन लोगों ने उससे यह बातें सुनींए उन्होंने इसे अस्वस्थए खतरनाक और परेशान करने वाला बताया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कथित योजना के वास्तविक क्रियान्वयन का कोई ठोस प्रमाण कभी सामने नहीं आया। न तो ऐसे किसी संगठित प्रजनन केंद्र के प्रमाण मिले और न ही ऐसे बच्चों केए जिन्हें निश्चयपूर्वक उससे जोड़ा जा सके। कुछ महिलाओं द्वारा यह दावा अवश्य किया गया कि वे उससे गर्भवती हुई थींए परंतु ये दावे न तो न्यायिक जांच में सिद्ध हो सके और न ही किसी वैज्ञानिक पुष्टि तक पहुँचे। इस प्रकार यह योजना विचारों और दावों के स्तर पर ही सिमटी रही। फ़िर भीए केवल इस आधार पर इसे महत्वहीन नहीं माना जा सकता। क्योंकि यह विचार उसी मानसिक संरचना से निकला थाए जिसने उसे व्यापक यौन अपराधों की ओर प्रवृत्त किया। उसकी दुनिया में संबंधों का कोई नैतिक अर्थ नहीं था। वहाँ केवल नियंत्रण थाए प्रभुत्व था और दूसरों की देह पर अधिकार जमाने की लालसा थी। उसका धन और सामाजिक पहुँच उसे यह भ्रम देती थी कि वह नियमों से ऊपर है और उसकी इच्छाएँ ही उसका विधान हैं।

इस पूरे प्रसंग में एक गहरी ऐतिहासिक छाया भी दिखाई देती है। मानव इतिहास में कई बार ऐसी विचारधाराएँ उभरी हैं जिनमें कुछ लोगों ने स्वयं को श्रेष्ठ मानकर दूसरों की तुलना में अधिक मूल्यवान समझा। ऐसी सोच ने नस्लीय भेदभावए अमानवीय प्रयोगों और व्यापक हिंसा को जन्म दिया है। एपस्टीन का विचार उसी खतरनाक परंपरा का आधुनिक और निजी रूप थाए जिसमें विज्ञान का मुखौटा पहनाकर अनैतिक इच्छाओं को? ठहराने की कोशिश की जाती है। यह भी उल्लेखनीय है कि एपस्टीन यह सब बातें अकेले में नहीं करता था। वह प्रभावशाली लोगोंए शिक्षाविदों और वैज्ञानिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के बीच इन विचारों को साझा करता था। यह तथ्य अपने आप में चिंताजनक हैए क्योंकि इससे यह संकेत मिलता है कि उसकी बातों को सुनने और सहने वाले लोग भी समाज के उच्च स्तरों में मौजूद थे। यद्यपि उनमें से कई ने बाद में दूरी बना लीए परंतु प्रारंभिक चुप्पी भी अपने आप में एक प्रश्न खड़ा करती है। बाद में जब उसके अपराध सार्वजनिक हुए और उससे जुड़े दस्तावेज़ सामने आएए तब इस कथित बेबी रैंच विचार को उसके समग्र व्यक्तित्व के संदर्भ में देखा जाने लगा। यह स्पष्ट हुआ कि यह कोई अलग या विचित्र कल्पना नहीं थीए बल्कि उसी मानसिकता का तार्किक विस्तार था जिसमें शक्ति का दुरुपयोग और इंसानी गरिमा की अवहेलना शामिल थी। उसके लिए लोग व्यक्ति नहीं थेए बल्कि संसाधन थे।इस पूरे मामले ने समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि जब अत्यधिक धन और प्रभाव किसी व्यक्ति के हाथ में बिना जवाबदेही के चला जाता हैए तो वह किस हद तक जा सकता है। यह केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं हैए बल्कि उस व्यवस्था पर भी प्रश्न है जो लंबे समय तक ऐसे लोगों को संरक्षण देती रहती है। एपस्टीन का पतन अचानक नहीं हुआय वह वर्षों तक एक ऐसी दुनिया में सक्रिय रहा जहाँ उसकी हरकतों को या तो अनदेखा किया गया या दबा दिया गया। अंततः बेबी रैंच का विचार चाहे वास्तविकता में न बदला होए परंतु उसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत गहरा है। यह हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञानए बुद्धि और प्रगति के नाम पर यदि नैतिकता को किनारे रख दिया जाएए तो परिणाम भयावह हो सकते हैं। मानव जीवन कोई प्रयोगशाला की वस्तु नहीं है और न ही किसी एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा का साधन। यह प्रसंग हमें सतर्क करता है कि किसी भी व्यक्ति को केवल उसकी संपत्तिए संपर्क या कथित प्रतिभा के आधार पर महान नहीं मान लेना चाहिए। असली मूल्य उस सोच में होता है जो मनुष्य को मनुष्य की तरह देखे। जेफ्री एपस्टीन का बेबी रैंच विचार इसी कसौटी पर पूरी तरह असफल सिद्ध होता है और इतिहास में एक चेतावनी की तरह दर्ज हो जाता है कि जब अहंकारए सत्ता और अनैतिक इच्छाएँ एक साथ मिलती हैंए तो कल्पनाएँ भी अपराध का रूप ले सकती हैं।

महेन्द्र तिवारी

स्वामी- स्वतंत्र प्रभात मीडिया, मुद्रक एवं प्रकाशक प्रीती शुक्ल द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला बिजय लक्ष्मी नगर परगना सौराचाद तहसील व जनपद सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, होनेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में तमे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोट:** उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादों का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.NI NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0-9511151254, E-Mail: news@swatantraprabhat.com

संक्षिप्त खबरें

श्री छत्रपाल बाबा पंडित बलभद्र प्रसाद माध्यमिक विद्यालय में बच्चों द्वारा रखा गया सुंदरकांड पाठ

बिसवां/सीतापुर श्री छत्रपाल बाबा पंडित बलभद्र प्रसाद माध्यमिक विद्यालय अल्लीपुर मे बच्चों द्वारा सुंदरकांड का पाठ रखा गया सुंदरकांड पाठ में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया उसके तत्पश्चात बच्चों ने मां शारदे का हवन भी किया जिसमें कई कवि और अतिथि भी उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन से बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया और एक नई राह दिखाने का प्रयास किया..उपस्थित अतिथि गण -डॉ हामिद अली कृषक इंटर कॉलेज मारु छी के प्रबंधक- अमन नबी अहमद जी, ग्राम पेड़रा के प्रधान- आलोक यादव जी और कई कविगण भी उपस्थित रहे- धर्मेंद्र धवल, अरविंद सिंह मधुप, घनश्याम शर्मा, विजय रस्तोगी, संदीप सरस, अरविंद त्रिपाठी, रजनीकांत दीक्षित रंजन, और विद्यालय में आए अतिथियों ने भी बच्चों को एक नया मार्गदर्शन दिया..बच्चों और विद्यालय के अध्यापकों ने बड़ी मेहनत और लगन से इस कार्यक्रम को एक नई दिशा दी विद्यालय परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद..

बसपा प्रमुख मायावती ने बजट सत्र में राज्यपाल के संबोधन को बताया निराशाजनक, कही ये बातें

» मायावती ने राज्यपाल के संबोधन को निराशाजनक करार दिया।

» विकास और जनहित पर ध्यान न देने की आलोचना की।

» गरीबी, बेरोजगारी और सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की।

लखनऊ। पूर्व मुख्यमंत्री एवं बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने विधानसभा के बजट सत्र में राज्य के संबोधन को निराशाजनक बताया। कहा कि उनका भाषण परंपरा से हटकर विकास एवं सर्वसमाज के उत्थान और जनहित में होना चाहिए था।

पूर्व सीएम ने एक्स पर लिखा है कि सरकार की गलत नीतियों से प्रदेश में करोड़ों लोग त्रस्त हैं। उन्हें गरीबी एवं बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इससे ज्यादा चिंता उन्हें अपने जान, माल और मजहब की है। राज्यपाल को इस विषय पर फोकस करना चाहिए था जिससे प्रदेश की जनता और विपक्ष को आश्वासन मिलता। मायावती ने लिखा है कि इसी वजह से विपक्ष लगातार नारेबाजी करता रहा। राज्यपाल के संबोधन में सरकार द्वारा जनहित के बड़े बड़े दावों, आश्वासनों एवं घोषणाओं व वादों को पूरा करने संबंधी विवरणों का अभाव लोगों की चिंता का कारण रहा। इसका आगामी बजट में समायोजन करना चाहिए।

उत्तर प्रदेश में 'सीखो करके' से संवरेंगी कक्षाएं, विज्ञान-गणित शिक्षक बनेंगे कौशल शिक्षक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा को रटंत से मुक्त कर प्रयोगधर्मी और कौशल-आधारित बनाने की दिशा में कोशिश हो रही है। 3288 चयनित परिषदीय विद्यालयों और डायट संस्थानों में 'लर्निंग बाय डूइंग' (सीखो करके) माडल को प्रभावी रूप से लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य बच्चों को किताबों तक सीमित न रखकर प्रयोग, गतिविधि और जीवन से जुड़े अनुभवों के माध्यम से सीखने के लिए प्रेरित करना है। इसी क्रम में उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ में 16 फरवरी से 18 मार्च तक विज्ञान और गणित विषय के 1400 शिक्षकों का त्रिदिवसीय आवासीय कौशल-आधारित प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण कुल 66 बैचों में पूरा होगा। इससे पहले 1880 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षित शिक्षक आगे अपने-अपने विद्यालयों में बच्चों को प्रयोग, प्रोजेक्ट, माडल और गतिविधि आधारित शिक्षण देंगे। विभाग का लक्ष्य बच्चों को केवल याद करने के बजाय समझने, परखने और खोजने की शिक्षा देना है। यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप है और भविष्य की स्किल-इकोनामी, नवाचार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग की जरूरतों को ध्यान में रखकर की जा रही है। शिक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, जब बच्चे स्वयं प्रयोग करते हैं और समाधान खोजते हैं तो उनकी जिज्ञासा, तार्किक सोच और समस्या-समाधान क्षमता का तेजी से विकास होता है। इससे बच्चे निष्क्रिय श्रोता के बजाय सक्रिय शिक्षार्थी बनते हैं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी ने कहा कि यह प्रयास बुनियादी शिक्षा में नई संस्कृति विकसित करेगा, जहां विद्यालय ज्ञान के साथ अनुभव की प्रयोगशाला बनेंगे। इससे उत्तर प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता मजबूत होगी और आने वाली पीढ़ी अधिक सक्षम व आत्मविश्वासी बनेगी।

धारदार हथियार से हमला दो युवक गंभीर रूप से घायल जन्मदिन पार्टी से लौट रहे युवकों पर हमला

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर के सदरपुर थाना इलाके में जन्मदिन कार्यक्रम से लौट रहे युवकों पर दबंगों ने धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने दो नामजद आरोपियों समेत चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस दौरान नाराज लोगों ने थाने पहुंचकर नाराजगी व्यक्त की जानकारी के अनुसार कोतवाली बिसवां क्षेत्र के मोहल्ला झज्झर निवासी विनीत कुमार मिश्रा, ललित दीक्षित और गौरव अग्निहोत्री रविवार रात करीब सवा ग्यारह बजे थाना सदरपुर के ग्राम धामी सरायं से जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होकर लौट रहे थे। रास्ते में देवियापुर में कुछ सामान लेने के लिए वे एक दुकान पर रुके। आरोप है कि इसी दौरान वहां मौजूद रिंकू रावत ने अकारण गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर रिंकू ने अपने साथी सुरेंद्र रावत और अन्य चार युवकों को बुला लिया और सभी ने मिलकर मारपीट शुरू कर दी। बताया जाता है कि रिंकू रावत ने विनीत कुमार मिश्रा के सिर पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़े। बीच-बचाव करने आए ललित दीक्षित के सिर पर तमंचे की बट से प्रहार किया गया, जिससे वह भी गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि हमलावरों ने विनीत की जेब से करीब साढ़े बारह हजार रुपये भी निकाल लिए। घटना का वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे साथी का मोबाइल फोन तोड़ दिया गया इसी दौरान गौरव ने किसी तरह गाड़ी स्टार्ट कर मौके से निकलने की कोशिश की तो आरोपियों ने लाठी-डंडों से वाहन पर हमला कर शीशे तोड़ दिए। आरोप है कि जब गाड़ी आगे बढ़ी तो हमलावरों ने पीछे से फायरिंग भी की। पीड़ित किसी तरह जान बचाकर देवियापुर चौकी पहुंचे और पुलिस को सूचना दी थाना सदरपुर पुलिस ने रिंकू रावत पुत्र प्रेमचंद, सुरेंद्र रावत तथा चार अज्ञात के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस का कहना है कि आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं!!

युवक की मौत मामले में तीन पर हत्या का केस दर्ज तालाब में मिला था शव

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में थानगांव थाना क्षेत्र में शनिवार सुबह तालाब में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। मृतक के पिता नरेश कश्यप की तहरीर पर गांव के ही शरीफ, खलील और शकील के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चोट के निशान और नाक से रक्तस्राव की पुष्टि हुई है। पुलिस की मौजूदगी में मृतक का अंतिम संस्कार कराया गया है। गौरतलब है कि शनिवार सुबह ग्रामीणों ने तालाब में एक शव उतराता देखा, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया वहां मौजूद लोगों ने उसकी पहचान 3 फरवरी से लापता 20 वर्षीय मनीष कश्यप पुत्र नरेश कश्यप निवासी थानगांव के रूप में की सूचना मिलते ही परिजन भी घटनास्थल पर पहुंच गए और हत्या की आशंका जताई। परिजनों और ग्रामीणों के अनुसार, 3 फरवरी की शाम मनीष को गांव के पास नव निर्मित पुलिया के निकट से संदिग्ध परिस्थितियों में उठाया गया था। इसके बाद से वह लापता था। आशंका है कि उसे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और शुक्रवार को उसकी हत्या कर दी गई। हत्या को छिपाने के उद्देश्य से शव को रात के अंधेरे में तालाब में फेंका गया शव मिलने पर नाक से खून बहने और शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए, जिससे परिजनों का शक और गहरा गया। थानाध्यक्ष विमल गौतम ने बताया कि युवक के लापता होने की सूचना मिलते ही पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है और आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा!!

नाम छिपाकर महिला से की शादी, मानसिक रूप से किया प्रताड़ित, गिरफ्तार

लखनऊ। सआदतगंज की एक कालोनी में रहने वाली महिला ने अपने पति पर नाम छिपाकर शादी करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। कन्नौज निवासी महिला ने आरोप लगाया कि 2010 में उसकी शादी हो चुकी थी। पहले पति से उसे एक बच्चा था। पति मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। 2015 में युवक ने उससे दोस्ती की और अपना नाम रितेश मौर्य बताकर शादी कर ली। इसके बाद किराये पर सआदतगंज इलाके में रहने लगा। 2018 में महिला गर्भवती हो गई। आरोपित उसे अपने माधौगंज हरदोई स्थित घर ले गया तो उसे पता चला कि युवक का असली नाम आरिफ है। इसके बाद महिला ने विरोध जताया लेकिन आरोपित ने डरा धमका कर शांत करा दिया। एक वर्ष पहले आसिफ उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगा। इसके बाद महिला ने हरदोई पुलिस से शिकायत की लेकिन सुनवाई नहीं हुई। थक हारकर उसने सआदतगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया। महिला ने अपने पिता से मिली कार हड़पने के भी आसिफ पर आरोप लगाए हैं इंस्पेक्टर संतोष कुमार आर्य ने बताया कि आरोपित आसिफ को गिरफ्तार किया गया है।

सीटेट में पांच सॉल्वर गिरफ्तार, बनारस में जेठानी की जगह देवरानी दे रही थी परीक्षा

लखनऊ। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटेट) के दूसरे दिन रविवार को वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, मऊ और प्रयागराज में दूसरे के स्थान पर परीक्षा देते पांच सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं। वाराणसी के सुभाषचंद्र महाविद्यालय में सीटेट की परीक्षा में आजमगढ़ निवासी अपनी जेठानी मंजू देवी के स्थान पर पात्रता परीक्षा देते समय देवरानी अर्चना यादव को पकड़ा गया। मऊ के अमृत पब्लिक स्कूल सहादतपुरा में प्रथम पाली की परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी बलिया के सोना सम्राट मौर्या के स्थान पर बलिया का ही निवासी सुशील कुमार वर्मा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर परीक्षा देते मिला। जौनपुर के प्रकाश ग्लोबल परीक्षा केंद्र से कुमारी गौतम को पकड़ा गया। प्रतापगढ़ की कुमारी गौतम जौनपुर निवासी नीलम यादव के स्थान पर परीक्षा दे रही थी। गाजीपुर के न्यू शाह फैज पब्लिक स्कूल में जीत यादव के स्थान पर पटना निवासी अंकित कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। प्रतापगढ़ में लालगंज तहसील क्षेत्र स्थित अझारा में पं. नागेश दत्त पब्लिक स्कूल में कौशांबी का रहने वाला संजय कुमार प्रतापगढ़ के परीक्षार्थी उमेश कुमार के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया। दोनों दोस्त हैं।

हरगांव क्षेत्र में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन, 817 मरीजों का हुआ इलाज

● हड्डी, हृदय, स्त्री व सांस रोगों की जांच, सर्जरी योग्य मरीज अस्पताल रेफर, आयुष्मान कार्ड से भी मिला लाभ

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

हरगांव सीतापुर (ब्यूरो)। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, श्री पीतांबरा शिक्षा समिति एवं पारा सराय स्थित के0 पी0 सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वावधान में ग्राम पंचायत सेलूमऊ की झरेखापुर बाजार में एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के गरीब, जरूरतमंद एवं ग्रामीण लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और निःशुल्क चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाया। चिकित्सा शिविर में वरिष्ठ सलाहकार ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. सुधीर कुमार चौधरी द्वारा हड्डी से संबंधित 113 मरीजों की जांच की गई, जिनमें से गंभीर मामलों को आवश्यक सर्जरी हेतु के0 पी0 सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल रेफर किया गया। वहीं डॉ. एस0 ए0 मीर (एमडी मेडिसिन) ने 52 हृदय रोगियों का कार्डियक परीक्षण कर उन्हें आवश्यक परामर्श एवं निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराई एवं श्वास संबंधी रोगों की जांच कर मरीजों को उपचार प्रदान किया गया। महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए डॉ. मधुलिका राय ने महिलाओं में बांझपन, ल्यूकोरिया एवं माहवारी से जुड़ी बीमारियों की जांच कर निःशुल्क दवाएं वितरित कीं। डॉ. फोजिया (स्त्री रोग विशेषज्ञ) द्वारा 93 महिलाओं का परीक्षण किया गया, जबकि डॉ. मोहम्मद इलियास (जनरल फिजिशियन) ने वायरल फीवर से पीड़ित 129 मरीजों की जांच कर उपचार किया।

शिविर में कुल 817 मरीजों का पंजीकरण कर उन्हें निःशुल्क जांच, परामर्श एवं दवाएं उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जनरल मैनेजर मुकेश बघेला एवं सीनियर मैनेजर नीतीश भीमटे द्वारा किया गया। आए हुए अतिथियों का स्वागत श्री पीतांबरा शिक्षा समिति के चेयरमैन डॉ. सुरेंद्र प्रताप सिंह ने किया। शिविर के सफल आयोजन में समिति के 12 पैरामेडिकल स्टाफ, 8 नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन एवं अन्य कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। स्वास्थ्य शिविर से लाभान्वित ग्रामीणों ने इस पहल की जमकर सराहना की और ऐसे आयोजनों को नियमित रूप से कराने की मांग की।

योगी बोले- कटे इसलिए थे क्योंकि बंटे थे फ़िर बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश में रोज़ दलित हिंदू मारे जा रहे

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

सीतापुर जनपद सीतापुर में सीएम योगी ने कहा- अगर सनातन पर संकट आएगा तो देश पर संकट आएगा। बंटोगे तो कटोगे। इसलिए बांटने वाले लोगों से सतर्क रहने की जरूरत है भूतकाल में गुलाम इसलिए हुए थे कि हम बंटे थे। भूतकाल में कटे इसलिए थे क्योंकि हम बंटे थे। बांग्लादेश में आज हिंदुओं की हालत किसी से छिपी नहीं है। वहां रोज दलित हिंदुओं की हत्या हो रही है। लेकिन देश के लोग चुप हैं। इसलिए हमें एकजुट रहना है। सीएम ने यहां तपोधाम आश्रम में गिरधारी नाथ महाराज स्मारक स्थल का अनावरण किया। गिरधारी नाथ महाराज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित शक्तिपीठ के संत रहे हैं। देश के बंटवारे के बाद उन्होंने सीतापुर में आकर अपनी साधना पूरी की थी। जिनकी याद में तपोधाम आश्रम में उनका स्मारक बनाया गया है अब नैमिष में महंत गिरधारी नाथ को भी जान सकेंगे सीएम ने कहा- जिस तरह पूर्वी भारत में शक्तिपीठ का महत्व है, वैसे ही पश्चिम में हिंगलाज का महत्व है। फिलहाल ये मंदिर पाकिस्तान में स्थित है। वहां हमारे बहुत कम लोग ही दर्शन करने जा पाते हैं। सीतापुर भारत के सनातन का पौराणिक स्थल है। भारत के पौराणिक स्थलों को पुनर्स्थापित करने का जिम्मा हमने लिया है। 3500 वर्ष पहले 88 हजार ऋषियों की तपोभूमि नैमिष में की थी और सभी ग्रंथ वही लिखा है। नैमिष ही महापुरुषों की तपस्थली है। अब यहां महंत गिरधारी नाथ को भी लोग जान सकेंगे। हमारे यहां चीटी को आंटा डालते हैं, ये सनातन की समानता सनातन में पहला ग्रास गो माता और अंतिम ग्रास कुत्ते को दिया जाता है। ये समता का व्यवहार है, जो सिर्फ भारत में मिलेगा। चीटी को भी लोग आटा डालते हैं। कितना भी जहरीला सांप हो उसे भी लोग नागमंचमी के दिन दूध पिलाते हैं। ये सनातन में ही संभव है। सनातन को तोड़ने का बहुत प्रयास हुआ। कुछ लोगों ने शरण तो ली लेकिन शरणार्थी धर्म नहीं निभाया। भारत की पूरी परम्परा इस से जुड़ी हैं, दुनिया की तमाम संस्कृति और सभ्यता समापत हो गई, लेकिन एक सांस्कृति दुनिया के सामने खड़ी और दुनिया को बसुधैव कुटुम्बकम का संदेश देने वाली हमारी सनातन परंपरा है। सनातन ने हर एक को बढ़ने का मौका दिया। मुगल आए, अंग्रेज आए, लेकिन जो लोग आए, धर्म और संस्कृति को लूटने का काम किया।

यहां जो भी आया, उसे शरण मिली, लेकिन कुछ लोगों ने यहां शरण लेकर शरणार्थी धर्म का पालन नहीं किया। उंगली पकड़ कर हाथ पकड़ने का काम किया, देश को लूटने का काम किया। पिछले 11 साल में देश ने तरक्की की चीन बढ़ रहा था और भारत को बढ़ाने का जो प्रयास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। मुगलों ने तो लूटा ही था और अंग्रेजों ने आश्रम पद्धति को खत्म करने का काम किया। देश 1947 में आजाद होता है, तब दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की भागीदारी महज 2 फीसदी रह गई थी पिछले 11 वर्षो में भारत की प्रगति देखा होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है। अब भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। अमेरिका और चीन के बाद भारत का नंबर होगा। 22 जनवरी को हर सनातनी की आंखें नम थीं 22 जनवरी 2024 के बाद भव्य राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दौरान हर भारतीय की आंखें नम थी। हर घर में दीप जल रहे थे और भारतीय दिवाली मना रहे थे। क्योंकि राम के साथ आत्मीयता का रिश्ता था। काशी में पहले 10 लोग एक साथ दर्शन नहीं कर पाते थे लेकिन अब देखिए कहीं कोई समस्या नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर बन गया। काशी में कॉरिडोर बन गया। देश में लोग बांग्लादेश पर कुछ नहीं बोलते सनातन कमजोर हो तो देश कमजोर होगा। जाति क्षेत्र और भाषा उसके सामने कोई मायने नहीं रखते। जो बांटने वाले लोग हैं उनसे सतर्क रहिएगा। ये लोग बांग्लादेश में रोज हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार पर कुछ नहीं बोलते। वो मरने वाला दलित हिंदू है। लेकिन कोई उसपर कुछ नहीं बोल रहा है। कुछ धर्माचार्यो और हिन्दू संगठनों को छोड़कर सब मौन हैं। दलित हिंदू पर सब मौन हैं। इन नेताओं के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। तमाम जातियों के नाम पर बांटना चाहते हैं। हम लोगों को सनातन को बचाना है देश का दुश्मन आंखे लगाए बैठा है कि कैसे आप बंटेंगे? हम भारतीयों का दायित्व बनता है कि हम भी उस यात्रा के साथ चले और सनातन की सुरक्षा करें। वर्तमान में जो सजग रहता है उसी का भविष्य भी उज्जवल होता है। भूतकाल में गुलाम इसलिए हुए थे कि हम बंटे थे, भूतकाल में कटे इसलिए थे क्योंकि हम बंटे थे। इसलिए बंटना नहीं है। वर्तमान में जो सजग रहता है उसी का भविष्य भी उज्जवल होता है!!

एस.जे.एस. में कक्षा 12 के छात्रों का भावपूर्ण विदाई समारोह संपन्न

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

लालगंज, रायबरेली। नगर के सर्वश्रेष्ठ व बहुचर्चित अंग्रेजी माध्यम शिक्षण संस्थान एस.जे.एस. पब्लिक स्कूल लालगंज में कक्षा 12 के छात्रों के सम्मान में भव्य एवं गरिमामय विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक अग्रज सिंह व सह प्रबंधिका डॉ अनुश्री सिंह द्वारा मां वीणा वादिनी की पूजा अर्चना तथा माल्यार्पण के साथ किया गया। विद्यालय की प्रधानाचार्या अंजू सिंह ने प्रबंधक तथा प्रबंधिका को फूलों का गुलदस्ता प्रदान कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात अपने स्वागत भाषण के साथ उन्होंने विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें जीवन में अनुशासन, परिश्रम और संस्कारों के महत्व से अवगत कराया। इस अवसर पर प्रधानाचार्या व प्रबंध समिति द्वारा कक्षा 12 के छात्रों को स्मृति चिन्ह व उपहार प्रदान किए गए। इसके उपरांत विद्यार्थियों के साथ भावनात्मक फोटो सेशन आयोजित किया गया जिसमें शिक्षकों और छात्रों की यादें कैमरे में कैद हुई। कार्यक्रम में कक्षा 11 के छात्रों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी गई। नृत्य संगीत और नाट्य प्रस्तुतियों ने उपस्थित जनसमूह को मंत्रमुग्ध कर दिया इसी के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी प्रभावशाली मंचन किया गया जिसने समारोह को यादगार बना दिया। इस अवसर पर विद्यालय की सह प्रबंधिका डॉ अनुश्री सिंह ने अपने प्रेरक अभिभाषण में छात्रों को आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने तथा विद्यालय की गरिमा बनाए रखने का संदेश दिया, वहीं विद्यालय के प्रबंधक अग्रज सिंह ने विद्यार्थियों को जीवन के नए पड़ाव के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि

सफलता के साथ-साथ नैतिक मूल्यों को अपनाना ही सच्ची उपलब्धि है। समारोह के अंत में विद्यालय की प्रधानाचार्या द्वारा धन्यवाद भाषण प्रस्तुत किया गया जिसमें उन्होंने सभी अतिथियों, शिक्षकों एवं छात्रों के सहयोग के प्रति आभार व्यक्त किया कार्यक्रम के इस अवसर पर कक्षा 11 तथा कक्षा 12 के समस्त छात्र तथा शिक्षक उपस्थित रहे।

सैकड़ों वर्ष पुराने प्राचीन शिव मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार, विशाल भंडारे में उमड़ा श्रद्धालुओं का जनसैलाब

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

महराजगंज, रायबरेली। महराजगंज तहसील क्षेत्र के सलेथू गांव में स्थित सैकड़ों वर्ष पुराने प्राचीन शिव मंदिर का ग्रामीणों के सहयोग से भव्य जीर्णोद्धार संपन्न हुआ। इस ऐतिहासिक और धार्मिक अवसर पर पूरे गांव में आस्था, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। मंदिर के जीर्णोद्धार के उपलक्ष्य में बीते आठ दिनों से निरंतर अपराजिता पाठ का आयोजन किया गया, जिसका विधिवत समापन सोमवार को हवन-पूजन और विशाल भंडारे के साथ हुआ।

कार्यक्रम के दौरान गांव सहित आसपास के क्षेत्रों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर प्रसाद ग्रहण किया। पूरे सलेथू गांव में धार्मिक उत्सव जैसा वातावरण बना रहा और 'हर-हर महादेव' के जयघोष से क्षेत्र गूंज उठा। इस पावन अवसर पर कार्यक्रम में पहुंचे महराजगंज तहसील के उपजिलाधिकारी गौतम सिंह ने मंदिर का अवलोकन किया और आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 'इतने सुविचारित, आस्था से जुड़े और ऐतिहासिक शिव मंदिर आज के समय में बहुत कम देखने को मिलते हैं। यह सलेथू गांव के लोगों का सौभाग्य है कि उन्होंने इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार कर भगवान शिव की सेवा की है। इससे निश्चित रूप से पूरे क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा और धार्मिक चेतना का संचार होगा। '

ग्रामीणों ने बताया कि यह शिव मंदिर वर्षों से क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र रहा है। यहां पीढ़ियों से लोग पूजा-अर्चना करते आ रहे हैं। मंदिर के जीर्णोद्धार से न केवल इसका धार्मिक महत्व और बढ़ा है, बल्कि गांव की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान भी और अधिक सुदृढ़ हुई है। कार्यक्रम को सफल बनाने में समस्त ग्रामवासियों का विशेष योगदान रहा।

आयोजन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, स्वच्छता और अनुशासन भी सराहनीय रहा, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हुई। इस अवसर पर उमेश तिवारी, रमाकांत तिवारी, अनु कोटेदार, आर.पी. साहू, मंडल अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव, शिवम मिश्रा, लालू सिंह, महबूब अली सहित हजारों की संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मंदिर के जीर्णोद्धार और इस भव्य आयोजन ने न केवल सलेथू गांव, बल्कि पूरे क्षेत्र में धार्मिक एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया है।

पतंग का जानलेवा मांझा रखने पर उत्तर प्रदेश में पहला एक्शन, लखनऊ में दो गिरफ्तारभारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 270 के तहत मुकदमा

युवकों के पास से पुलिस कांच लगा मांझा बरामद

लखनऊ । उत्तर प्रदेश में पतंग के गैर परंपरागत मांझा से बढ़ती दुर्घटनाओं और जनहानि पर मुख?यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद एक्शन हो गया है। दुकान में जानलेवा चाइनीज मांझा रखने के मामले में लखनऊ में पुलिस ने पहली बार दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगातर सख्ती के बाद प्रदेश में पुलिस ने जानलेवा चाइनीज मांझा के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा ने भी पुलिस पर इस चाइनीज मांझा रखने वालों के खिलाफ धरपकड़ करने का निर्देश दिया।

सख्ती के तहत चाइनीज मांझा रखने के मामले में लखनऊ में पुलिस ने पहली बार दो लोगों को गिरफ्तार किया है! बाजारखाला इलाके में दो युवकों के पास से पुलिस कांच लगा मांझा बरामद किया है। युवकों की पहचान लखनऊ में शहीद पथ के पास स्थित मलेसेमऊ गांव निवासी सदफ अली और अयान खान के रूप में हुई है। दोनों के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 270 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से मांझे की चरखी मिली है।

नंदकिशोर कैलाशचंद महाविद्यालय टिकरा के सात दिवसीय विशेष शिविर का भव्य समापन

● सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण रैली एवं प्रतिभावान स्वयंसेवकों का हुआ सम्मान

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

बिसवां/सीतापुर नंदकिशोर कैलाशचंद महाविद्यालय, टिकरा बिसवां (सीतापुर) की राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) इकाई द्वारा चयनित ग्राम में आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर का समापन रविवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं पर्यावरण जागरूकता गतिविधियों के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। शिविर के अंतिम दिन स्वयंसेवकों द्वारा पर्यावरण संरक्षण विषय पर जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें स्वच्छता, हरियाली और पर्यावरण संतुलन का संदेश दिया गया। इसके पश्चात शिविर स्थल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने देशभक्ति, सामाजिक चेतना और लोकसंस्कृति पर आधारित प्रस्तुतियाँ देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। मध्यान्ह भोजन के उपरांत विधिवत रूप से शिविर का समापन किया गया। इस अवसर पर महाविद्यालय के संरक्षक डॉ. सुधाकर वर्मा एवं संस्था के डायरेक्टर संतोष वर्मा उपस्थित रहे। डॉ. सुधाकर वर्मा ने अपने संबोधन में कहा– 'राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से विद्यार्थियों में सेवा, अनुशासन और सामाजिक दायित्व की भावना विकसित होती है। इस शिविर में स्वयंसेवकों ने जिस निष्ठा और समर्पण से कार्य किया है, वह सराहनीय है। '

वहीं संस्था डायरेक्टर संतोष वर्मा ने कहा– 'शिविर के दौरान बताए गए कार्यों को जीवन में उतारना ही NSS की सच्ची सफलता है। स्वयंसेवकों का श्रमदान और अनुशासन प्रेरणादायक रहा। ' शिविर के दौरान श्रमदान किया गया तथा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले श्रेष्ठ स्वयंसेवकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस सात दिवसीय विशेष शिविर का सफल संचालन दलनायकों के नेतृत्व में संपन्न हुआ दलनायक मनीष वर्मा समापन अवसर पर सभी स्वयंसेवकों ने शिविर से प्राप्त अनुभवों को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बच्चों को मोबाइल से दूर रहने की सलाह, कहा-मन से पढ़ो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों को लेकर बेहद गंभीर हैं। लखनऊ या गोरखपुर में भी जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को फोकस देश के भविष्य पर ही रहता है। उनका बच्चों से संवाद और उनका दुलार काफी चर्चा में रहता है। लखनऊ में सोमवार को बजट सत्र पर जाने से पहले मुख्यमंत्री ने 'जनता दर्शन' में प्रदेशभर से आए लोगों के साथ पहुंचे बच्चों को बड़े काम की सलाह दी। उन्होंने से अभिभावकों के साथ आए बच्चों को दुलारा। इसके बाद उनको चाकलेट दी और कहा कि मोबाइल से दूर रहना और खूब मन लगाकर पढ़ना। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा कि मोबाइल पर गेम और रील आपका कीमती समय चुरा रहा है। मुख्यमंत्री ने बच्चों से कहा है कि वे किताबों से दोस्ती करें। जनता दर्शन में हापुड़ से आए दो सैनिकों ने मुख्यमंत्री से बताया कि पिता के नेत्रहीन होने और घर पर कोई न रहने से जमीन ताऊ के लड़कों ने कब्जा कर लिया है। ताऊ के लड़के हथियार के बल पर धमकी देते हैं। मुख्यमंत्री ने हापुड़ प्रशासन को मामले की तत्काल जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा। मुख्यमंत्री के समक्ष कुछ लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की मांग लेकर भी पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि आप हॉस्पिटल से एस्टिमेट बनवाकर दें, सरकार इलाज में हरसंभव मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि आप मरीज के स्वास्थ्य की चिंता कीजिए, इलाज की चिंता सरकार की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त बिजली, नगर निगम, राजस्व आदि से जुड़े मामले भी आए।

संक्षिप्त खबरें

सिद्धार्थनगर बोलेरो ई रिक्शा में टक्कर, एक की मौत, दो महिला सहित तीन घायल

सिद्धार्थनगर। जिले के इटवा थाना क्षेत्र के ग्राम घोपलापुर के पास सोमवार की दोपहर एक तेज रफ्तार बोलेरो ने सामने से आ रहे ई-रिक्शा को टक्कर मार दी। इस हादसे में ई-रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो महिला यात्री गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक ई-रिक्शा चालक की पहचान कठेला समय माता थाना क्षेत्र के ग्राम गुरौवाजोत निवासी दिलसाद पुत्र इसरार के रूप में हुई है। दिलसाद अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य था। उसकी मौत की खबर से परिवार में कोहराम मच गया। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे।

बताया जाता हैं की बोलेरो तेज गति में थी और चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया था। टक्कर इतनी भीषण थी कि ई-रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। ई-रिक्शा में सवार दो घायल महिलाओं की पहचान खानकोट निवासी सुशीला (40) और बलरामपुर जनपद के मधवानगर निवासी उर्मिला (35) के रूप में हुई है। दोनों को तत्काल सिद्धार्थनगर मेडिकल कॉलेज भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों ने उनकी हालत गंभीर बताई है।हादसे में बोलेरो चालक जय प्रकाश (50) भी गंभीर रूप से घायल हो गया। बोलेरो में चालक सहित कुल पांच लोग सवार थे। दुर्घटना के बाद बोलेरो में सवार चार अन्य लोग मौके से फरार हो गए। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में थानाध्यक्ष रविंद्र सिंह का कहना है कि मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजादिया गया हैं और मामले की जांच की जा रही हैं।

सीडीओ ने ब्लाक बेलखरनाथधाम का किया निरीक्षण, शिकायत निस्तारण और साफ-सफाई का दिया निर्देश

विकास योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ किया जाए-सीडीओ

प्रतापगढ़। मु य विकास अधिकारी डा0 दिव्या मिश्रा ने आज बाबा बेलखरनाथधाम विकास खंड कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त श्रम एवं रोजगार संतोष कुमार सिंह तथा खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र बहादुर सिंह अपने अधीनस्थ स्टाफ के साथ उपस्थित रहे। निरीक्षण में मु य विकास अधिकारी ने कार्यालय परिसर की नियमित साफ-सफाई के निर्देश के साथ मनरेगा, आवास योजना और स्थापना पटल सहित सभी योजनाओं की पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उन्होंने खंड स्तर पर तैयार जन सूचना रजिस्टर, शिकायत रजिस्टर, डिस्पैच रजिस्टर, कैश बुक और ग्रांट रजिस्टर की भी जांच की और खंड विकास अधिकारी को सभी रजिस्टरों को शासन द्वारा निर्धारित चेकलिस्ट के अनुसार अद्यतन पूर्ण करने का निर्देश दिया। प्राप्त शिकायतों का तीन कार्य दिवसों के भीतर निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और ग्राम में लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाए।

जमीन पर अवैध कब्जा कर धमकाने का आरोप

ललितपुर। सौजना थाना क्षेत्र में भूमि पर अवैध कब्जे, मारपीट और जान से मारने की धमकी के गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया गया है। ग्राम सौजना निवासी बृजकिशोर पुत्र स्व.देवी प्रसाद की शिकायत पर थाना सौजना में शिकायत दर्ज की गई है। मामला बीएनएस की धाराओं ×29(×), 111(7), ×52 और ×51(×) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। बृजकिशोर के अनुसार सौजना-मड़ावरा मार्ग स्थित उनके ×0 बाई 40 वर्गफुट के आवासीय प्लॉट (खाता सं या 2427/5) पर 28 जुलाई 2025 को आरोपियों द्वारा संगठित रूप से बलपूर्वक बजरी व गिट्टी डालकर गैरकानूनी कब्जा कर लिया गया। ×0 जुलाई 2025 को जब पीड़ित ने कब्जा हटाने का विरोध किया तो आरोपियों ने मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित का आरोप है कि पहले की गई शिकायतों पर स्थानीय स्तर पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद न्यायालय की शरण ली गई। न्यायालय के आदेश पर थाना सौजना ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जपदीय सिंचाई बन्धु की बैठक 10 फरवरी को

प्रतापगढ़। जनपदीय सिंचाई बन्धु की बैठक दिनांक 10 फरवरी 2026 को पूर्वान्ह 11 बजे सिंचाई खण्ड कार्यालय में की जायेगी। बैठक की अध्यक्षता अधिशासी अभियन्ता/सचिव सिंचाई बन्धु अरविन्द वर्मा द्वारा की जायेगी। बैठक में जनपद के जनप्रतिनिधिगण, जनपदीय अधिकारी एवं कृषकगण आमंत्रित है।

आदिवासी छात्रवास निर्माण में भू-माफिया बने बाधा, निर्माण कार्य रुकवाकर मजदूरों को दी धमकी

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

शहडोल। जिले के छतवई क्षेत्र में बन रहे आदिवासी बालक-बालिका छात्रावास के निर्माण कार्य में भू-माफियाओं द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने का गंभीर मामला सामने आया है। इस संबंध में स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत सौंपकर कड़ी दंडात्मक कार्यवाही की मांग की गई है।

क्या है पूरा मामला?

शिकायत के अनुसार, संदीपनी शा.उ.मा.वि. छतवई में दूर-दराज से आने वाले आदिवासी छात्र-छात्राओं के लिए मध्य प्रदेश शासन की आराजी खसरा नंबर 2019 पर छात्रावास का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि क्षेत्र के कुछ रसूखदार और अतिक्रमणकारी इस सरकारी जमीन को हड़पने की नीयत से निर्माण कार्य में बाधा डाल रहे हैं।

जातिसूचक गालियां और धमकी का आरोप

शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया है कि बीती 25 जनवरी 2026 की सुबह लगभग 10-11 बजे कुछ चिन्हित व्यक्तियों ने निर्माण स्थल पर पहुंचकर मजदूरों को डराया-धमकाया। आरोप है कि इन लोगों ने अभद्र भाषा और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा कि वे यहाँ छात्रावास नहीं बनने देंगे। मजदूरों को काम छोड़ने पर मजबूर किया गया और उन्हें वहां से भगा दिया गया।

धर्म की आड़ में जमीन कब्जाने की कोशिश

शिकायतकर्ताओं का कहना है कि ये लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करने के उद्देश्य से वहां भागवत, रामायण और रामलीला जैसे आयोजनों का बहाना बना रहे हैं। साथ ही, पास की अन्य सरकारी भूमि (खसरा नंबर 1980/1, 1979) पर भी अवैध तरीके से फेंसिंग कर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है।

पुलिस से सुरक्षा और कार्यवाही की मांग

शिकायत में स्पष्ट किया गया है कि आरोपी पक्ष काफी धनवान और प्रभावशाली है, जो असामाजिक तत्वों का सहारा लेकर निर्माण कार्य रुकवा रहा है। इससे न केवल सरकारी कार्य में बाधा आ रही है, बल्कि भविष्य में किसी अप्रिय घटना की आशंका भी बनी हुई है। ग्रामीणों और संबंधित विभाग ने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि दोषियों पर तत्काल एफआईआर दर्ज की जाए ताकि छात्रवास का निर्माण सुचारू रूप से पूरा हो सके।

यमुना खादर में अवैध निर्माण पर एनजीटी सख्त, एमसीडी-डीडीए समेत कई विभागों को भेजा नोटिस

नई दिल्ली। मजनू का टीला क्षेत्र में यमुना नदी के खादर क्षेत्र में अवैध निर्माण होने के खिलाफ एक स्थानीय नागरिक द्वारा भेजे गए पत्र का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने स्वतः संज्ञान लिया है। एनजीटी ने माना कि पत्र में पर्यावरणीय मानदंडों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया गया है। एनजीटी ने प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए नगर निगम दिल्ली (एमसीडी), संबंधित जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को मामले में पक्षकार बनाते हुए नोटिस जारी किया। एनजीटी ने जिलाधिकारी को अवैध निर्माण करने वालों को विवरण देने के साथ ही यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि क्या निर्माण यमुना खादर क्षेत्र में हुआ है। उक्त निर्देश के साथ मामले की सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सिलापथार में सौदों असम मटर श्रमिक फेडरेशन का प्रेस वार्ता

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

असम धेमाजी। सौदों असम मोटर वर्कर्स फेडरेशन ने रविवार शाम को सिलापथार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देश में मोटर वर्कर्स को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देश में मोटर वर्कर्स को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है असम सरकार ने पारित किया मटर श्रमिक कानून को शीघ्र प्रत्याहार करना। मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स प्रोटेक्शन एक्ट को तुरंत लागू करना, डेंजरस मोटर व्हीकल (अमेंडमेंट) एक्ट 2019 को रद्द करना, बि एन एस हिट एंड रन धारा 106(ख) को रद्द करना, श्रमिक-विरोधी लेबर कोड को रद्द करने की मांगो को लेकर यूनियन ने प्रेस वार्ता कर 12 फरवरी में 24 घंटे के चक्का बंद का आह्वान किया है। बंद के दौरान एंबुलेंस, टेस्ट और इमरजेंसी सर्विस को बंद से छूट दी जाएगी। प्रेस वार्ता में सौदों असम मटर श्रमिक फेडरेशन के सचिव जून सोनोवाल, सौदों असम कमर्शियल परिवहन संस्था के सचिव रंजन गोगोई, मटर श्रमिक संस्था के धेमाजी जिला के सहलाकर किरण गोगोई, सिलापथार मैक्सिकन एसोसिएशन के सचिव गोबिन हजारिका सहित कार्यकर्ता मौजूद थे।

चाय बागान में चाय बागान श्रमिकों को भूमि पट्टा हेतु आवेदन पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ अधिकारियों, विधायक एवं बागान प्रबंधक की उपस्थिति में किया गया

● मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बागान श्रमिकों के कल्याण हेतु भूमि आवंटन एवं पट्टा प्रदान करने की यह पहल एक ऐतिहासिक क्षण की साक्षी है : विजय मालाकार।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि श्रीभूमि जिले के दुल्लभछड़ा चाय बागान मैदान में श्रमिकों के लिए भूमि योजना हेतु आवेदन पत्र वितरण कार्यक्रम का औपचारिक शुभारंभ किया गया। 9 फरवरी (सोमवार) को आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक विजय मालाकार, जिला प्रशासन के अधिकारी, रामकृष्णनगर सर्कल अधिकारी तथा चाय बागान के प्रबंधक की उपस्थिति में चाय बागान के महिला एवं पुरुष श्रमिकों को भूमि पट्टे के आवेदन पत्र वितरित किए गए। जिला प्रशासन की ओर से बताया गया कि जिन योग्य चाय-श्रमिक परिवारों को भूमि व्यवस्था का लाभ मिलेगा, उनके लिए यह आवेदन पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। आज दोपहर लगभग 2 बजे से जिले के विभिन्न चाय बागानों में आयोजित फॉर्म वितरण कार्यक्रमों के दौरान लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा का भाषण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी अतिथियों का क्रमशः गमछा पहनाकर स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर विधायक विजय मालाकार ने अपने संबोधन में कहा, 'असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के नेतृत्व और दूरदर्शिता में कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत चाय बागान मजदूरों को भूमि आवंटन और पट्टा प्रदान करने की यह पहल श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 'उन्होंने श्रमिकों से निर्धारित समय के भीतर आवेदन पत्र सही ढंग से भरकर जमा करने की अपील की। कार्यक्रम में रामकृष्णनगर उपजिला प्रशासन के अधिकारी, सीडीसी निलुतपल पाठक, रामकृष्णनगर सर्कल ऑफिसर सौभिक दत्त, चाय बागान प्राधिकरण के प्रतिनिधि शिरीष तिवारी, सहायक दूल्लभछड़ा जिला परिषद सदस्य प्रणव मुखर्जी, जीपी के प्रतिनिधि, दूल्लभछड़ा जीपी अध्यक्ष देव कुमार कुर्मी, सहित बड़ी संख्या में चाय बागान के महिला एवं पुरुष श्रमिक सदस्य उपस्थित रहे।

कोलंबो में आयोजित सेपक टकराव चैंपियनशिप में भारत का पांच स्वर्ण पदक जीतना अप्रत्याशित: पेरिका सुरेश

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता
स्वतंत्र सिंह भुल्लर

नई दिल्ली। कोलंबोश्रीलंकामें आयोजित साउथ एशिया सेपक टकराव चैंपियनशिप में भारत के पुरुष एवं महिला सेपक टकराव खिलाड़ियों ने पांच स्वर्ण पदक जीत कर इतिहास रच दिया है।अभी हाल ही में टोक्यो में आयोजित एशियाई खेल 2026 के टेस्ट इवेंट में भारतीय पुरुष सेपक टकराव टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। भारतीय सेपक टकराव टीम की इस अप्रत्याशित जीत पर साउथ एशिया सेपक टकराव ऑर्गेनाइजेशन के प्रेसिडेंट एस.आर.प्रेम राज जी, सेपक टकराव फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट जी.श्रीनिवासलू,संयुक्त सचिव सेपक टकराव फेडरेशन ऑफ इंडिया पेरिका सुरेश एवं जनरल सेक्रेटरी नरेश कुमार ने समस्त खिलाड़ियों, कोच, मैनेजमेंट स्टाफ और सेपक टकराव फेडरेशन फैमिली के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक जीत सेपक टकराव खेल को मजबूत पहचान देगा तथा युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा एवं ऊर्जा का काम करेगा। संयुक्त सचिव पेरिका सुरेश ने कहा कि सेपक टकराव की प्रबंधन समिति के कुशल नेतृत्व में यह खेल तेजी से लोकप्रियता के नए-नए मुकाम प्राप्त कर रहा हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खेलो इंडिया खेलो के सपनों को साकार करते हुए भारत के खिलाड़ियों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कराई हैं। भारत में यह खेल लोकप्रियता के नए- नए कीर्तिमान बनाएं तथा युवाओं के लिए खेल भावना के प्रसार का स्रोत बने, इसी कामना के साथ मैं इस जीत पर समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं।

तीस हजारी कोर्ट में वकील से मारपीट पर HC सख्त, सत्र न्यायाधीश से मांगी रिपोर्ट; पुलिस को दिए सुरक्षा के निर्देश

» हाई कोर्ट ने तीस हजारी सत्र न्यायाधीश से रिपोर्ट मांगी।

» पुलिस को संबंधित अधिवक्ता को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश।

» अदालत परिसर सुरक्षा पर चिंता, एसीपी जांच का आदेश।

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने तीस हजारी कोर्ट के अंदर एक वकील से मारपीट मामले में तीस हजारी कोर्ट के सत्र न्यायाधीश से रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया। अदालत ने साथ ही मामले में जांच रिपोर्ट आने तक पुलिस को संबंधित अधिवक्ता को सुरक्षा प्रदान करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने संबंधित डीपीसी से पूछा कि अदालत परिसर में वकील को पीटा जाती है, आखिरी अदालत की सुरक्षा कैसे हो रही है। अदालत ने भी कहा कि मामले में की गई प्राथमिकी की जाए एक एसीपी स्तर के अधिकारी द्वारा डीसीपी की देखरेख में की जाएगी। यह मामला सोमवार को तब सामने आया जब वकील ने मामले को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने उल्लेख किया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए अधिवक्ता को हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शिकायत करने को कहा था।

पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष खीरी उस्मानिया खातून के कार्यकाल को सराह रहे लोग

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

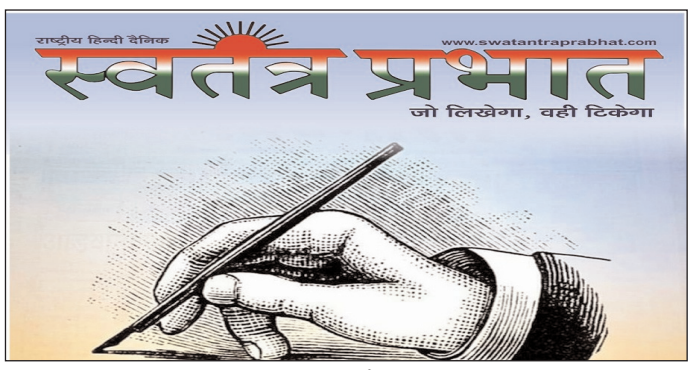

नगर पंचायत खीरी में यूँ तो बहुत से अध्यक्षो का कार्यकाल जनता ने देखा लेकिन वर्ष 2006 से लेकर 15 नवम्बर 2011 तक श्रीमती उस्मा पूर्व नगर पंचायतो खातून पत्नी श्री अफ़ज़ल अली गौरी के कार्यकाल को आज भी नगर पंचायत खीरी का ऐसा सुनहरा कार्यकाल कहा जाता है जिसकी लोग समय समय पर मिसालें देते रहते हैं। जी हाँ अपने निर्भीक और निष्पक्ष फैसलों के लिए चर्चित तत्कालीन अध्यक्ष उस्मानियाँ खातून का नाम कस्बावासी एक आयरन लेडी के रूप में लेते हुए उनके कई निष्पक्ष फैसलों और उनके कार्यकाल की बहुत सी विशेषताओं का बखान करते नहीं थकते हैं।

श्रीमती उस्मानियाँ खातून के कार्यकाल में अनगिनत विकास कार्य बिना किसी भेदभाव के हुए और अवैध अतिक्रमण तो किसी हालत में भी बरदाश्त ही नहीं किये गए। इस आयरन लेडी के कार्यकाल की एक ऐसी विशेषता रही जो किसी भी अध्यक्ष के कार्यकाल में नहीं रही। वो विशेषता ये थी कि पूरे पाँच वर्षों में किसी भी अवैध अतिक्रमणकारी को कभी नोटिस जारी नहीं किया गया बल्कि जहाँ भी जिसने भी अवैध अतिक्रमण किया तो खबर पाते ही चैयरपर्सन खुद नगर पंचायत अमले के साथ मौके पर पहुंचती थी और सारा अवैध अतिक्रमण साफ करवा देती। मोहल्ला शेखसराय, स्टेशन रोड और गन्ना रोड पर उनके कार्यकाल में असर और रसूख वाले लोगों द्वारा किये गए अवैध अतिक्रमणों को कड़ाई और निडरता से धराशाई कराना आजतक लोगों की जुबानों पर रहता है। किसी अवैध अतिक्रमणकारी को कभी लिखित नोटिस नहीं भेजे जाने की बात केवल हवा हवाई नहीं है बल्कि नगर पंचायत खीरी के डिस्पैच रजिस्टर को देखकर आज भी इस बात की पुष्टि की जा सकती है।

श्रीमती उस्मानियाँ खातून के कार्यकाल में भू माफियाओं को उनकी ऐसी औकात बता दी गई थी कि तत्कालीन ई ओ से आर्थिक सांठगांठ बना लेने के बाद भी किसी भू माफिया की हिम्मत नहीं हुई कि वह इस आयरन लेडी को दौलत का लालच देकर नगर के किसी भी तालाब की पटाई करके प्लाटिंग करने का साहस कर पाता। श्रीमती उस्मानियाँ खातून के कार्यकाल के खत्म होते ही कस्बे के कई तालाबों को भू माफिया निगल गए। कस्बे की जल निकासी और वर्षा ऋतु में जो पुराने तालाब वरदान साबित होते थे, एक एक करके सभी का वजूद खत्म कर दिया गया और आज उनपर इमारतें बनी दिख रही हैं और बहुत से तालाबो पर पटाई के बाद प्लाटिंग का काम जारी है। मिसाल के रूप में स्थानीय पुलिस चौकी के सामने का नज़ारा ही देख लिया जाए जहाँ अब करोड़ो की कीमत में प्लाटिंग की जा चुकी है और बहुत सी इमारतें बन चुकी हैं और कई भवन बन रहे हैं इसी स्थान पर वर्तमान में नगर पंचायत द्वारा निर्माणाधीन पार्क ज़बरदस्त विवादों के घेरे में है। मालूम हो कि क़स्बा वासी चश्मदीद हैं कि इस विशाल इलाके में एक विशाल प्राचीन तालाब हुआ करता था। श्रीमती उस्मानियाँ खातून के कार्यकाल मे ज़िला मुख्यालय के कुछ भू माफियाओं का एक अमला तालाब के पास आया और पटाई का काम शुरू किया तो खबर लगते ही अध्यक्ष उस्मानियाँ खातून और उनके पति अफ़ज़ल गौरी अपने चौपहिया वाहन से मौके पर पहुंचे और असलहों से लैस भू माफ़ियाओं पर एक शेरनी की तरह गरजने वाली उस्मानियाँ खातून और जनहित में किसी हद तके चले जाने के मामले में मशहूर उनके पति अफ़ज़ल गौरी ने चेतावनी देते हुए फौरन नज़र के सामने से दफा होने को कहा।

चश्मदीद बताते हैं कि उन माफियाओं की सिट्टी पिटटी गुम हो गई और सब के सब मिनटों में अपने साज़ो सामान सहित ऐसा गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींघ। और उस्मानियाँ खातून के अध्यक्ष रहते उन माफियाओं ने कभी पलटकर कस्बे का रुख तक नहीं किया।

अगर नगर के विकास की बात की जाए तो जीता जागता उदाहरण विद्युत पावर हाउस मौजूद है जो इसी आयरन लेडी की कार्यकुशलता का प्रतीक है। बुद्धिजीवियों का आज भी मानना यही है कि इस पावर हाउस को जिस ज़मीन पर बनवाया गया था उस जमीन पर कुछ लोगों द्वारा पावर हाउस बनने नहीं दिया जा रहा था और ज़बरदस्त विवादों के कारण विद्युत विभाग ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे लेकिन निर्भीख और निडर उस्मानियाँ खातून और उनके पति ने मौके पर मौजूद रहकर पूरी कड़ाई के साथ पावर हाउस का निर्माण कराया और आपत्ति का रोड़ा अटकाने वालों को मौके से रफू चक्कर ही होना पड़ा। आज वही विद्युत पावर हाउस क़स्बा खीरी और आस पास के इलाके के लिये एक वरदान साबित हो रहा है।

उसूलों से कभी समझौता न करने वाली, बड़े से बड़े असरदार के रोब में नहीं आने वाली, फास्ट डिसीजन लेने वाली, अनुशासन के मामले में काफी सख्त, इस आयरन लेडी के कार्यकाल को आज भी खीरी टाउन के नागरिक याद करते हैं। यूँ तो नगर पंचायत खीरी की अध्यक्ष की कुर्सी पर समय समय पर बहुत से अध्यक्ष आए और चले गये, सभी ने अपने अपने कार्यकाल में क़स्बा खीरी की बेहतरी के काम अपने अपने तरीके से किये लेकिन जिस गरिमा के साथ उस्मानियाँ खातून ने यहाँ अध्यक्ष पद को सुशोभित किया है वो नगर पंचायत खीरी के इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में ऐसा दर्ज हो गया है कि नगर पंचायत खीरी का नाम आते ही जब नए पुराने सभी अध्यक्षों की चर्चा होती है तो पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सय्यद अहसन रिज़वी के बाद अगर किसी अध्यक्ष का कार्यकाल याद किया जाता है तो वो कार्यकाल नगर पंचायत खीरी की पूर्व अध्यक्ष उस्मानियाँ खातून का ही कार्यकाल था।

असम विश्वविद्यालय में अत्यधिक वर्षा और जोखिम प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

श्रीभूमि: उत्तर पूर्व में बढ़ती जलवायु अनिश्चितता की पृष्ठभूमि में, 9 फरवरी (सोमवार) को असम विश्वविद्यालय में 'अत्यधिक वर्षा और जोखिम प्रबंधन' (E&treme Rainfall and Risk Management) विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई। इस कार्यशाला का आयोजन भौतिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। एक प्रतीकात्मक और पर्यावरण के अनुकूल पहल के रूप में, मेघनाद साहा सम्मेलन कक्ष में एक पौधे को जल अर्पित कर कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन किया गया।

उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर राजीव मोहन पंत ने की। इस अवसर पर गुवाहाटी स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक सुनीता दास, कछार जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सलाहकार डॉ. राजीव गुप्ता और अगरतला मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉ. पार्थ रॉय सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। स्वागत भाषण देते हुए, स्कूल ऑफ फिजिकल साइंसेज के डीन और कार्यशाला के समन्वयक प्रोफेसर अत्री देशमुख ने कार्यक्रम की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। भौतिकी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर हिमाद्री शेखर दास ने वर्तमान जलवायु परिदृश्य के संदर्भ में ऐसी विशेष कार्यशालाओं के महत्व और आवश्यकता पर बल दिया। कुलपति प्रोफेसर पंत ने आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन में शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कार्यशाला की प्रासंगिकता को रेखांकित किया.यह कार्यशाला भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के संरक्षण में आयोजित की जा रही है। संसाधन व्यक्तियों (Resource persons) में त्रिपुरा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के शरत चंद्र दास और कछार डीडीएमए के फील्ड ऑफिसर रणविजय दास शामिल हैं। कार्यशाला में कुल 40 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं, जो वर्षा जनित जोखिमों और उनके तकनीकी पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। उद्घाटन कार्यक्रम का संचालन भौतिकी विभाग की छात्रा सुष्मिता सिन्हा ने किया।

घर का ताला तोड़कर चोरी

ललितपुर। थाना जाखलौन क्षेत्र के ग्राम कचरौंदा घाट में एक महिला के घर का ताला तोड़कर चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम कचरौदा घाट निवासी गिंदा पत्नी लाखन लोधी ने थाना जाखलौन में दी गई तहरीर में बताया कि 6 फरवरी 2026 को वह घरेलू सामान खरीदने के लिए ललितपुर गई थीं। शाम लगभग 4 बजे घर से निकलने के बाद जब वह रात में वापस लौटीं तो देखा कि उनके घर का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था। पीड़िता के अनुसार घर के अंदर रखे बक्से से सोने की हाय (पीली धातु), लगभग 25-×0 किलोग्राम गेहूं तथा 200 रुपये नकद चोरी हो गए। मामले की जानकारी करने पर पता चला कि उक्त चोरी मनीष पुत्र हरदास राजक निवासी सेरनीकलां, थाना जाखलौन द्वारा की गई है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की धारा ×05 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है।

नकली एंटी-कैंसर दवाओं पर शिकंजा, दिल्ली में 25 फर्मों से 55 सैंपल जब्त; औषधि नियंत्रण विभाग की बड़ी कार्रवाई

● नकली एंटी-कैंसर दवाओं के खिलाफ दिल्ली में अभियान।

25 फर्मों से 55 सैंपल जब्त, 6 पर कार्रवाई।

स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

नई दिल्ली। नकली एंटी-कैंसर दवाओं की जांच के लिए दिल्ली औषधि नियंत्रण विभाग ने सोमवार को अभियान चलाकर 25 फर्मों से 55 सैंपल एकत्र किए। इनमें 33 लीगल सैंपल और 22 स्पेसिमन सैंपल हैं। नियमों के उल्लंघन पर छह फर्मों पर नियमानुसार कार्रवाई आरंभ की दी गई है। जांच पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी व उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के लक्ष्मी नगर, यूसुफ सराय, ग्रीन पार्क, ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, पश्चिम विहार, द्वारका और रोहिणी आदि में अस्पताल क्षेत्रों और फार्मास्यूटिकल बाजार में की गई। कार्रवाई जीवनरक्षक एंटी कैंसर दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने व मरीजों की सुरक्षा के उद्देश्य से दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. पंकज सिंह के निर्देश पर की गई। सभी को लैबोरेटरी टेस्टिंग और एनालिसिस के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, ताकि किसी भी सब-स्टैंडर्ड या नकली दवा का बाजार में सर्कुलेशन रोका जा सके। डा. पंकज सिंह ने कहा कि एंटी-कैंसर दवाएं अत्यंत क्रिटिकल और लाइफ सेविंग होती हैं, जिनमें गुणवत्ता से समझौता मरीजों की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। इसी कारण दवा आपूर्ति सप्लाई चेन पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है।

डॉ. पंकज ने कहा कि दिल्ली सरकार की नीति नकली और घटिया दवाओं के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की है। ऐसे अभियान नियमित रूप से चलते रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता और स्वास्थ्य संस्थानों का आह्वान किया कि वे दवा केवल पंजीकृत केंद्रों से ही खरीदें और शक होने पर उसकी सूचना तुरंत औषधि नियंत्रण विभाग को दें।